स्वतंत्र छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ से प्रकाशित एक सम्पूर्ण पत्रिका

प्रेरणा स्त्रोतः

जी. स्वामी (रायपुर)

प्रधान संपादकः

जी. भूषण राव

समाचार संपादकः

जी.वी.एस. रूक्मणि देवी

उप संपादकः

राखी श्रीवास्तव

सलाहकार संपादकः

रविश बेंजामिन

अशोक तोमर

मार्केटिंग हेडः

शैलेन्द्र दवे

मार्केटिंग प्रतिनिधिः

हरिमोहन तिवारी

आवरण सज्जाः

Infinity

ब्यूरो हेडः

बिलासपुरः विनीत चौहान

जशपुरः आनंद गुप्ता

कोरियाः प्रवीण निशी

बस्तरः सुनील सिंह राठौर

आफिसः

बी-13, बसंत पार्क

अनमोल सुपर मार्केट के पास

महावीर नगर, न्यू पुरेना रायपुर छ.ग.

ईमेलः swatantrachhattisgarh@gmail.com

वेबसाईटः www.swatantrachhattisgarh.com

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक

जी. भूषण राव द्वारा सागर प्रिंटर्स, पुरानी बस्ती रायपुर द्वारा मुद्रित एवं बी-13, बसंत पार्क, अनमोल सुपर मार्केट के पास, महावीर नगर, न्यू पुरेना, रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित

मो.:- 99934-54909

संपादकः जी. भूषण राव

पत्रिका में प्रकाशित लेख, लेखकों के अपने विचार है, किसी भी विवाद की स्थिति में सुनवाई का क्षेत्र रायपुर होगा।

वार्षिक सदस्यता शुल्क सभी

(विशेषांकों सहित प्रस्तावित) 132/-रू.मात्र

Pg 3

मानानीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का स्वतंत्रता दिवस संदेश
पुलिस परेड ग्राउण्ड , रायपुर...

Pg 10

भारत का केंद्रीय बजट 2024-25- मुख्य विशेषताएं...

Pg 17

सुविधाओं के नाम पर भारी पड़ रही बैंकों की वसूलियां ...

Pg 24

अडानी के बाद सेबी निशाने पर क्यों ?

Pg 34

हमेशा की तरह पीएम मोदी ने अपने भाषण में नेशन फर्स्ट की बात कही ...

3.0 का पहला बजट वास्तविक और भविष्योन्मुखी

तीसरी बार सता में आने के बाद पेश किये गए बजट में कुछ नया जोड़ने का प्रयास दिखा। कहा जा सकता है कि वित्तीय अभियांत्रिकी कुशलता और राजनीतिक प्रबंधन का सटीक प्रबंधन दिखता है। जिसमे हमेशा की तरह लोक-लुभावन घोषणाओं के बजाय वित्तीय अनुशासन और अथव्यवस्था को मजबूत बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। विशेषकर नौजवाओं का वक्त नज़र आया। हमारे देश की वित्त मंत्री सीतारमण ने संसद में लगातार सातवाँ और मोदी 3.0 का पहला बजट प्रस्तुत करते हुवे उम्मीदों के अनुरूप लोक लुभावन घोषणाओं के बजाय वित्ते अनुशासन और अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने वाले दूरगामी क़दमों पर जोर दिया है। उन्होंने बजट भाषण में मोदी सरकार के नौ प्राथमिकताएं बतायी ,जो कृषि की उत्पादकता व लचीलापन,रोजगार व कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय ,विनिर्माण और सेवायें,शहरी विकास ,ऊर्जा सुरक्षा,बुनियादी ढांचा,नवाचार,अनुसन्धान व विकास और अगली पीढी के सुधार हैं, और यही इस नए बजट का आधार भी है।

बजट में शिक्षा और रोजगार पर विशेष ध्यान देते हुवे कौशल प्रशिक्षण से जुडी विशिष्ट योजनाओं की घोषणा की है। जिसके तहत अगली पांह वर्ष में करीबन एक करोड़ युवाओं को हुनरमंद बनाया जाएगा। इसके अलावा आयकर चुकाने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी मानक कटौती 50000 से बढाकर 75000 रुपये किये जाने का प्रस्ताव है। राजस्व बढ़ोतरी के लिये लॉन्ग-टर्म केपिटल गेन टैक्स को 10 से 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

बिहार और आंध्र-प्रदेश के लिए क्रमशः 58900 करोड़ एवं 15000 करोड़ की घोषणा की गयी है। जिसके कारण रोजगार तो बढेगा ही साथ ही कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। कृषि के लिए पिछ्ली बार की तुलना में 21.6 प्रतिशत अधिक 150000 करोड़ रुपयों की घोषणा की गयी है ।

नया बजट वास्तविक और भविष्य के अनुरूप है। क्योकि हमेशा की तरह पेश किये गए बजट में कुछ नया जोड़कर स्थायित्व पर ध्यान दिया गया है। जो कि मजबूर नीव रखता नजर आता है।

आपका अपना
भूषण राव

देश के 78 वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी छत्तीसगढ़वासियों को हार्दिक बधाई...

माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का स्वतंत्रता दिवस संदेश

पुलिस परेड ग्राउण्ड , रायपुर...

आज स्वतंत्रता दिवस की इस मंगल बेला में हम सभी स्वाधीनता का सुख साझा कर रहे हैं। हमको यह आजादी अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध हमारे पूर्वजों के कठिन संघर्ष और बलिदान के बूते मिल पायी है। यह आजादी हमें देन है शहीद गेंद सिंह, शहीद धुरवा राव, शहीद यादव राव, शहीद वेंकट राव, वीर गुंडाधुर, शहीद डेबरी धुर, शहीद आयतु माहरा, शहीद वीर नारायण सिंह जैसे हमारे अनेक ऐतिहासिक नायकों की, जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए जनमानस में स्वाधीनता की अलख जगायी।महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश के स्वाधीनता सेनानियों के साथ ही छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भारत माता की परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए जो अनथक मेहनत की, उसके सुखद परिणाम स्वरूप आज हम स्वतंत्र वातावरण में साँस ले रहे हैं।

स्वाधीनता के साथ ही बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान निर्माण का काम संपन्न हुआ, जो आज प्रकाश स्तंभ की तरह देश के लोकतंत्र को निरंतर आगे बढ़ने की राह दिखा रहा है। बरसों पहले बाबा गुरु घासीदास जी ने समता मूलक समाज का आदर्श हम सबके सामने रखा था, जो बाबा साहेब द्वारा निर्मित संविधान में फलीभूत हुआ। उनके संविधान में कबीर की वाणी का सार भी है, जो भारत के नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-साथ समानता प्रदान करती है।

आज के दिन हम उन पूर्वजों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिन्होंने आपातकाल के कठिन दौर में संविधान की मशाल को बुझने नहीं दिया। देश भर में हजारों लोकतंत्र सेनानियों ने इमरजेंसी का विरोध किया और इसके प्रतिरोध में जेल की सजा और अन्य यातनाएँ भुगतीं। अगले वर्ष 25 जून को इमरजेंसी के पचास बरस पूरे हो जाएंगे। इस वर्ष ''आपातकाल स्मृति दिवस'' के अवसर पर 25 जून के दिन हमें अपने प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों का आशीर्वाद मिला है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अपने लोकतंत्र सेनानियों के प्रति कृतज्ञता-ज्ञापित करने हेतु पिछले पांच वर्षों से रुकी उनकी सम्मान निधि हमारी सरकार द्वारा पुनः प्रारंभ की गई है।

आज के दिन हम अपने उन जवानों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जो हमारे प्रदेश में लोकतंत्र विरोधी, नक्सलवादी आतंक से पूरे साहस और जज्बे के साथ मुकाबला कर रहे हैं। बीते आठ महीनों में हमारे जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 146 नक्सलियों को मार गिराया है। इस दौरान हमने 32 नये सुरक्षा कैंप खोले हैं और आने वाले दिनों में 29 नये कैंप शुरू करने जा रहे हैं। आज कई वर्षों बाद क्षेत्र की जनता सुरक्षित महसूस कर रही है, जिसका कारण हमारे वीर जवानों की मेहनत व पराक्रम है। नक्सलवादी घटनाओं से निपटने के लिए अनुसंधान और अभियोजन की कार्रवाई और भी प्रभावी रूप से हो सके, इसके लिए हमने राज्य अन्वेषण एजेंसी (एसआईए) का गठन किया है। बस्तर की जनता नक्सलियों से त्रस्त हो चुकी है और विकास के मार्ग पर सरपट दौड़ने को तैयार है।

अन्दरूनी क्षेत्रों में नये कैंपों का विस्तार कर लोगों को आतंक से मुक्ति देने के साथ ही इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसके लिए हमने ' 'नियद नेल्लानार'' योजना शुरू की है। इस शब्द का अर्थ होता है -''आपका

अच्छा गांव''। विशेष पिछड़ी जनजातियों के हितग्राहियों के लिए आरंभ की गई ''पीएम जनमन योजना'' की तरह इस योजना से कैंपों के निकट पांच कि.मी. की परिधि के गांवों में 17 विभागों की 53 हितग्राही मूलक योजनाओं एवं 28 सामुदायिक सुविधाओं का लाभ लोगों को दिया जा रहा है। इन गांवों में पहली बार लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं। वे शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सरकार की लोकहितकारी योजनाओं का लाभ अब उठा रहे हैं। उनके जीवन में सुशासन का नया सवेरा आया है।

हमें अपने जवानों के साथ अपने किसानों पर भी गर्व है। उनके श्रम से छत्तीसगढ़ महतारी का धान का कटोरा भरा-पूरा रहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी के अनुरूप हमने अन्नदाताओं की सुख-समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे प्रेरणा पुंज अटल जी के जन्मदिन ''सुशासन दिवस'' के अवसर पर हमने राज्य के 13 लाख किसानों के बैंक खाते में 3716 करोड़ रुपए का बकाया धान बोनस अंतरित किया। हमने अपने वायदों को पूरा करते हुए किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की। प्रदेश में ''रिकॉर्ड'' 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई। किसानों को समर्थन मूल्य की 32 हजार करोड़ रुपए की राशि के साथ ही कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत प्रदेश के 24 लाख 75 हजार किसानों को अंतर की राशि 13 हजार 320 करोड़ रुपए अंतरित किए गए। इस प्रकार हमारे अन्नदाताओं के खाते में सरकार ने धान खरीदी और बकाया बोनस मिलाकर लगभग 49 हजार करोड़ रुपए अंतरित किए।

भूमिहीन किसानों को हमने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत 10 हजार रुपए वार्षिक सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। प्रदेश में कृषि हितैषी नीतियों की वजह से खेती-किसानी में रौनक लौट आई है और किसानों के चेहरों पर मुस्कान नजर आ रही है। आज हमारे गांव आर्थिक रूप से संपन्न नजर आते हैं। एक लोककल्याणकारी सरकार के लिए इससे बढ़कर संतोष की बात और कुछ नहीं हो सकती।

छत्तीसगढ़ को गढ़ने और सँवारने में मातृशक्ति की अहम भूमिका है। हम उनके योगदान का वंदन करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में तीज त्योहार की परंपरा है। तीजा के मौके पर भाई अपनी बहनों को भेंट देते हैं। प्रदेश की माताओं-बहनों को ''महतारी वंदन योजना'' के रूप में यही भेंट हम प्रदान कर रहे हैं। 10 मार्च, 2024 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल समारोह में 70 लाख माताओं-बहनों के खाते में महतारी वंदन योजना की पहली किश्त के रूप में एक-एक हजार रुपए की राशि अंतरित की। अब तक इस योजना की छह किश्त जारी की जा चुकी है।

हमारी माताएं-बहनें इससे आर्थिक रूप से सक्षम व आत्मनिर्भर हुई हैं। वे इस राशि का उपयोग अपनी इच्छा अनुसार बच्चों की पढ़ाई एवं घर के बजट को व्यवस्थित करने में कर रही हैं, जिससे उन्हें आर्थिक संबल मिल रहा है। जब हम बेटियों को मजबूत करते हैं तो पूरा परिवार मजबूत होता है और मजबूत परिवार से ही मजबूत समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। महिलाओं के आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरण से निश्चित ही विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला मजबूत हो रही है।

एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हमारे समक्ष अंत्योदय के लिए कार्य करने का आदर्श रखा है। समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति के उत्थान और विकास को सुनिश्चित करने के इसी लक्ष्य के अनुरूप हम अनथक कार्य कर रहे हैं। अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी 68 लाख परिवारों को अगले पांच सालों तक नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय हमारी सरकार द्वारा लिया गया है।

आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें सबसे पहले सबको आवास सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी है। मैं पिछले तीन दशकों से विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा के निकट संपर्क में रहा हूँ, उनके करीब रहकर मैंने देखा है घास-फूस के आवास में रहने वालों का दर्द क्या होता है।

जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना लेकर आए तो प्रदेश के लाखों परिवारों को उम्मीदें जगी लेकिन पिछले 5 सालों में प्रदेश के 18 लाख जरूरतमंद परिवारों के आवास का सपना पूरा नहीं हो सका। हमने संकल्प लिया कि हम इन 18 लाख परिवारों की पीड़ा दूर करेंगे। शपथ लेने के अगले दिन ही हमारी सरकार ने इनके आवास के सपने को पूरा करने की राह खोल दी। इसके साथ ही सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में चिन्हांकित 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों को आवास स्वीकृत करने का निर्णय भी हमने ''मुख्यमंत्री आवास योजना'' के तहत लिया है।

सबको आवास के साथ ही सबको शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जलजीवन मिशन भी आरंभ किया है। प्रदेश में इसके क्रियान्वयन की दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। इसके लिए हमने 4500 करोड़ रुपए का बजट रखा है। प्रदेश में भू जल की समस्या वाले गांवों में जलजीवन मिशन के अंतर्गत मल्टी विलेज स्कीम के माध्यम से पेयजल आपूर्ति का काम शुरू हो गया है। फिलहाल राज्य के 18 जिलों में 70 मल्टी विलेज योजनाओं का काम आरंभ हो गया है। हमने छत्तीसगढ़ में 50 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा था। मुझे खुशी है कि इसमें से 39 लाख 31 हजार परिवारों में हम नल कनेक्शन उपलब्ध करा चुके हैं।

हमारे ग्रंथों में ''सर्वे संतु निरामया'' की कामना की गई है। किसी तरह की बीमारी हो जाने पर सबसे ज्यादा चिंता आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उठानी पड़ती है। इसे देखते हुए प्रदेश में ''आयुष्मान भारत''-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना'' के साथ ही ''शहीद वीरनारायण सिंह स्वास्थ्य योजना'' लागू करने का निर्णय लिया गया है। इन दोनों योजनाओं से छत्तीसगढ़ के 77 लाख 20 हजार परिवारों को 5 लाख रूपए तक नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है।

वन अधिकार पत्र धारकों की मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके वारिसों को वन अधिकार पत्र हस्तांतरित करने की प्रक्रिया का उल्लेख वन अधिकार नियमों में नहीं था। इस वजह से नामांतरण, सीमांकन, खाता विभाजन जैसे राजस्व संबंधी कार्य संभव नहीं थे। हमने अपने जनजाति और वनवासी भाइयों की पीड़ा को समझा। हमारी सरकार द्वारा उनके वारिसों को वन अधिकार पत्र हस्तांतरित करने का प्रावधान किया गया है। अब वन अधिकार पत्र धारण करने वाले हमारे जनजाति और वनवासी भाइयों के लिए सीमांकन, नामांतरण, खाता विभाजन जैसे कार्य सहज हो गये हैं। इन वन अधिकार पत्रों को डिजिटलाइज्ड भी किया गया है।

जनजातीय क्षेत्रों में वनधन केंद्रों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने वनोपज संग्राहकों की आर्थिक तरक्की की नई राह खोली है। हमारी सरकार ने राज्य के तेंदूपत्ता संग्राहकों की पारिश्रमिक दर को 4000 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए कर दिया है। साथ ही तेंदूपत्ता संग्रहण समय सीमा में भी वृद्धि की गई, जिससे हमारे भाई-बहन अधिक समय तक तेंदूपत्ता संग्रहण कर बढ़ी हुई आय अर्जित कर

पा रहे हैं। इस साल 13 लाख 5 हजार तेंदूपत्ता संग्राहकों को 855 करोड़ 80 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। इनकी संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 1 लाख 72 हजार अधिक है।

युवा हमारे भविष्य हैं। युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिले, उनकी उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त वातावरण हो, इसके लिए हम प्राथमिकता से कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार यह मानती है कि भर्ती प्रक्रियाओं में की गई अनियमिततायें होनहार युवकों को रोजगार के अवसरों से वंचित तो करती ही हैं, साथ ही इससे सिविल सेवा की गुणवत्ता पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है।

हमारी सरकार द्वारा राज्य सिविल सेवा परीक्षा 2021 में हुई अनियमितता की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय लिया गया। हम युवाओं के लिए समान अवसर और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित हैं। यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में हमारे युवाओं की सफलता दर बढ़े, इसके लिए आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग द्वारा नई दिल्ली में संचालित यूथ हॉस्टल में यूपीएससी की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों के लिए सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर हमने 185 कर दी है।

अब सिविल सेवाओं की तैयारी के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के चयनित युवा पूर्णत: नि:शुल्क कोचिंग प्राप्त कर सकेंगे एवं दिल्ली में कहीं भी निवास करने पर उनको निर्धारित स्टाइपेंड भी प्राप्त होगा जिससे उन्हें किराये के लिए भी प्रतिपूर्ति प्राप्त होती रहेगी। हमने शासकीय सेवाओं हेतु आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की है। इससे प्रदेश के लाखों युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। राजधानी के नालंदा परिसर की तरह ही 13 और नगरीय निकायों में सर्वसुविधायुक्त लाइब्रेरी भी तैयार की जाएगी।

युवाओं के लिए खेल की सर्वोत्तम अधोसंरचना तैयार करने की दिशा में हमारी सरकार द्वारा गहन प्रयास किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमने ''छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना'' आरंभ करने का निर्णय लिया है।

रायगढ़ जिले में इंडोर स्टेडियम काम्प्लेक्स, हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान एवं सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक 31 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा, वहीं बलौदाबाजार जिले में 14 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम काम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। जशपुर जिले के कुनकुरी में 33 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से आधुनिक खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। निश्चित रूप से हमारी सरकार युवाओं को उन्नति के लिए हर अवसर प्रदान करेगी, यह हमारा संकल्प है।

रोजगार के बेहतर अवसर अच्छी शिक्षा से उत्पन्न होते हैं। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की नींव को ठोस करने का काम हमने शुरू कर दिया है। इसके लिए प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ अपनी बोली-भाषा की विविधता से समृद्ध है। हमारे यहां कहावत प्रचलित है कि ''कोस-कोस मा पानी बदलय, चार कोस मा बानी।'' प्रारंभिक आयु में बच्चे सबसे ज्यादा अपनी मातृभाषा में सीखते हैं, इसके चलते ही हमने नई शिक्षा नीति के तहत 18 स्थानीय भाषाओं में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई कराने का निर्णय लिया है। इससे बच्चों का अपनी भाषा से अनुराग भी बढ़ेगा तथा हमारी नई पीढ़ी अपनी जड़ों से भी जुड़ी रहेगी।

स्कूलों की अधोसंरचना को बेहतर करने एवं यहां शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रथम चरण में प्रदेश के 211 स्कूलों में पीएमश्री योजना आरंभ की गई है। इन स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। तीसरे चरण में हमें 52 स्कूलों की स्वीकृति मिली है। हम ग्रीन स्कूल तैयार कर रहे हैं।

स्कूलों में स्थानीय भाषाओं के साथ रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसे विषय भी पढ़ाये जा रहे हैं, ताकि विद्यार्थी नये समय के अनुरूप स्वयं को तैयार कर सकें। प्रदेश के स्कूलों में न्यौता भोज का आयोजन भी शुरू किया गया है। इसमें जन्मदिन जैसे विशेष अवसरों पर स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने समाज की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। इससे बच्चों का पोषण विकास तो होता ही है, सामुदायिक भावना का भी विकास होता है। पैरेंट्स-टीचर मीटिंग के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में हम काम कर रहे हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हमने उच्च शिक्षा में भी अपनाया है। इसके चलते हमारे पाठ्यक्रम रचनात्मक होने के साथ ही रोजगारमूलक भी होंगे ताकि नये समय की जरूरतों के अनुरूप मानव संसाधन उपलब्ध कराये जा सकें और युवाओं को बेहतर रोजगार मिल सके। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए हमने ''छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन'' का गठन किया है। हम आईआईटी की तर्ज पर प्रदेश के हर लोकसभा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी संस्थान आरंभ करने जा रहे हैं। इसके लिए पहले चरण में रायपुर, रायगढ़, बस्तर, कबीरधाम और जशपुर में इनकी स्थापना की जाएगी।

प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति को मजबूत करने मेडिकल शिक्षा का लगातार विस्तार जरूरी है। हमने संभाग स्तर पर एम्स की तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आरंभ करने का निर्णय लिया है। रायपुर में मेकाहारा तथा बिलासपुर में सिम्स के भवन विस्तार तथा अन्य सुविधाओं पर काम प्रारंभ कर दिया है।

युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करते हुए अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने हेतु हम प्रदेश की नई उद्योग नीति तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हम देश की जानी-मानी विशेषज्ञ संस्थाओं तथा उद्योग संगठनों की सलाह लेकर कार्य कर रहे हैं। औद्योगिक अवसरों को आगे बढ़ाने देश-दुनिया में जो नवाचार प्रारंभ किये गये हैं, उन्हें राज्य की परिस्थिति के अनुरूप लागू करने छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार

परिषद के गठन का निर्णय भी हमने लिया है।

राज्य में निवेश का बेहतर माहौल हो, इसके लिए हमने सिंगल विंडो सिस्टम को नवीनीकृत किया है। इससे उद्यमियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य क्लियरेंस के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नेशनल हाइवे, एयरपोर्ट और रेलवे कनेक्टिविटी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, उससे छत्तीसगढ़ अब निवेश के लिए सबसे आदर्श जगह बन गया है। यहां प्रचुर खनिज संसाधन, कानून-व्यवस्था की बेहतर स्थिति और कुशल मानव संसाधन के बूते उद्योगों के फलने-फूलने की प्रचुर संभावनाएं हैं।

प्रदेश की भौगोलिक विविधता को देखते हुए हमने सभी क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए रणनीति तैयार की है। बस्तर और सरगुजा में हम वनोपज प्रसंस्करण केंद्रों, इको टूरिज्म, नैचुरोपैथी आदि पर जोर दे रहे हैं। नवा रायपुर को हम आईटी हब तथा इनोवेशन हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। राजधानी के समुचित विकास के लिए और यहां उद्यम के अवसरों को बढ़ावा देने हम नेशनल कैपिटल रीजन(एनसीआर) की तरह ही स्टेट कैपिटल रीजन विकसित करने जा रहे हैं। कोरबा-बिलासपुर इंडस्ट्रियल कारिडोर बनाने का निर्णय हमने लिया है। इसके अस्तित्व में आने पर इन क्षेत्रों में औद्योगिक विस्तार और भी तेज हो जाएगा। उद्यमी युवाओं को ''छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना'' के माध्यम से 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ हम ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेंगे।

हमारी सरकार पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिखाई गयी सुशासन की राह पर चलकर छत्तीसगढ़ को संवार रही है। सुशासन के मूल्यों को क्रियान्वित करने हमने ''सुशासन एवं अभिसरण विभाग'' का गठन किया है। यह विभाग शासन-प्रशासन के हर स्तर पर पारदर्शिता, नवाचार और सुशासन का कार्यान्वयन सुनिश्चित कर रहा है। योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की प्रभावी मानिटरिंग के लिए हमने ''अटल मॉनिटरिंग ऐप'' भी तैयार किया है।

प्रशासन के हर स्तर पर पारदर्शिता लाने के लिए हम विभागों में 266 करोड़ रुपए की लागत से आईटी टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें अपनाने से मानवीय त्रुटि एवं कूटरचना की आशंका समाप्त हो जाएगी। यह पारदर्शिता की ओर सरकार द्वारा उठाया गया सबसे बड़ा कदम है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस की हमारी नीति को कार्यान्वित करने में इससे बड़ी मदद मिल रही है।

गवर्नेंस के हर हिस्से में हम पारदर्शिता सुनिश्चित कर रहे हैं। खनिजों के परिवहन में हमने मैनुअल पद्धति को समाप्त कर दिया है और ई-ट्रांजिट पास जारी करने की व्यवस्था पुनः शुरू की है। इसी तरह सरकारी खरीदी में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हमने जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदी का निर्णय लिया। आबकारी नीति में पारदर्शिता लाने तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने, पुरानी व्यवस्था के स्थान पर सीधे कंपनियों से खरीदी का निर्णय लिया है।

राजस्व संबंधी प्रकरणों के त्वरित और समय-सीमा में निराकरण के लिए हमने तहसीलदारों के अधिकारों का विस्तार किया है। नाम, जाति, पता की त्रुटि, सिंचिंत-असिंचित रकबा, कैफियत त्रुटि, एक

फसली-बहु फसली त्रुटि को सुधारने का अधिकार तहसीलदार को दिया गया है, जिससे राजस्व संबंधी परेशानी झेल रहे लोगों की दिक्कत दूर हो रही है।

केन्द्र की तर्ज पर राज्य नीति आयोग का गठन किया गया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आजादी के सौ बरस पूरे होने पर वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया है। हमारी सरकार भी इससे कदमताल करते हुए ''विकसित छत्तीसगढ'' का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। इसके लिए राज्य नीति आयोग द्वारा ''अमृतकाल विजन 2047'' तैयार किया जा रहा है। हमारी दिशा स्पष्ट है, नियत साफ है और हौसला पर्वत जैसा है। निश्चित ही आप सभी की भागीदारी के साथ ''अमृतकाल विजन 2047'' पर काम कर हम विकसित छत्तीसगढ़, विकसित भारत के निर्माण का संकल्प पूरा करेंगे।

छत्तीसगढ़िया लोगों की पहचान देश-दुनिया में सहज-सरल लोगों के रूप में है। यह हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हम मेहनतकश लोग हैं। ईमानदारी से काम करते हैं। यह हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं। इन्हें सहेज कर रखना हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। अपनी बोली-भाषा, तीज त्यौहार, खान-पान को सहेजते हुए आने वाली पीढ़ी को इनसे परिचित कराते हुए हमें निरंतर आगे बढ़ना है।

जलवायु परिवर्तन के संकट को देखते हुए हम सबका कर्तव्य है कि पर्यावरण को बेहतर बनाने में अपनी भागीदारी दें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान आरंभ किया है। मैंने अपने गृह ग्राम बगिया में इस अभियान के अंतर्गत रुद्राक्ष का पौधा लगाया है। रायपुर में मुख्यमंत्री निवास में मैंने दहीमन का पौधा लगाया है। आप भी एक पौधा जरूर लगाएं, यह आग्रह है।

यह हमारी पुण्य भूमि का परम सौभाग्य है कि श्रीराम हमारे भांजे हैं और उनकी कर्मभूमि भी छत्तीसगढ़ है। मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के सीतामढ़ी हरचौका से लेकर सुकमा के इंजरम तक कण-कण श्रीराम के वनवास काल का साक्षी है। हमारी धरती, माता शबरी की पुण्य भूमि है। पवित्र शिवरीनारायण धाम में उन्होंने अपनी अगाध श्रद्धा से जूठे बेर प्रभु को खिलाए थे। वनवास के दौरान बिताए गए चौदह वर्षों में से दस वर्ष प्रभु श्री राम ने हमारे छत्तीसगढ़ में ही बिताए हैं। रामायण के प्रसंग जनजातीय लोगों से प्रभु श्रीराम के अद्भुत स्नेह तथा प्रभु श्रीराम के जनजातीय लोगों के प्रति गहन अनुराग और समर्पण से भरे पड़े हैं। हम जब भी इन प्रसंगों को सुनते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। हम धन्य हैं कि हमारा जन्म इस पुण्य भूमि में हुआ है। यह सौभाग्य हमें श्रीराम के आदर्शों पर चल कर निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है।

पांच सौ वर्षों के अहिंसक संघर्ष की पूर्णाहुति अयोध्या धाम में श्रीरामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के रूप में हुई। अपने भांचा राम के दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ का हर नागरिक उत्सुक है। ''अयोध्या धाम श्रीरामलला दर्शन योजना'' के माध्यम से हम हजारों रामभक्तों को उनके आराध्य के दर्शन के लिए पूर्णतः निःशुल्क भेजने का माध्यम बने हैं। यह पुण्य अवसर हमें श्रीरामलला ने दिया है।

तुलसीदास जी ने लिखा है- ''दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुहि ब्यापा।'' भगवान श्रीराम ने एक आदर्श राज्य की स्थापना की। आप सभी के सहयोग से हम अपने पूरे सामर्थ्य के साथ काम करते हुए छत्तीसगढ़ को सुखी, समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में काम करेंगे।

बहनों एवं भाइयों,

लोकतंत्र में भरोसे का संकट सबसे बड़ा संकट होता है। यह तंत्र निश्चित ही जनता का अपने प्रतिनिधियों पर भरोसा कायम रखने से ही चलता है। कार्यभार संभालने के बाद हमारी सबसे बड़ी चुनौती इसी भरोसे को बहाल करने की थी। हमे इस अवसर पर यह कहते हुए संतोष हो रहा है कि हमारी सरकार ने आपसे किये अधिकांश बड़े वायदों को पूरा कर इस विश्वास को फिर से स्थापित किया है। हमारे संविधान निर्माताओं का सपना ऐसे ही मजबूत लोकतंत्र का था, जहां जनता और उसकी चुनी सरकार भरोसे की ऐसी ही मजबूत डोर में बंधी रहे। वास्तव में यह लोकतंत्र का मजबूत रक्षासूत्र है, जिसे कभी भी किसी भी लोकसेवक को कमजोर नहीं करना चाहिए।

हमारे राज्य निर्माता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय स्वर्गीय अटल जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण प्रदेश के व्यापक आर्थिक विकास एवं प्रदेश की सुंदर संस्कृति के संरक्षण के लिए किया। हमारा दायित्व है कि 'हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे' के संकल्प के साथ प्रदेश के नवनिर्माण के महती कार्य में पूरी लगन से जुट कर अटल जी का सपना साकार करें।

स्वतंत्रता दिवस का यह दिन हमें स्मरण कराता है कि हमें मिली आजादी बहुमूल्य है। पूर्वजों ने कठिन संघर्ष और बलिदान देकर स्वतंत्रता की विरासत हमें सौंपी है। हमारे पूर्वजों ने भारत माता को परतंत्रता की बेड़ियों से आजाद कर देशभक्ति की अनुपम मिसाल प्रस्तुत की। विकसित भारत के निर्माण में अपनी सहभागिता प्रदान कर देश को संवारने के अनुकरणीय कार्य में अपना योगदान देकर हम पूर्वजों की इस परंपरा को आगे बढ़ाने का यश हासिल कर सकते हैं, यही हमारा कर्तव्य भी है।

विपक्ष को जनता की परेशानी का ध्यान रखना चाहिए...

(जी.वी.एस.रुक्मणि देवी)

राजनीतिक दल चुनाव हार जाते हैं तो जनता उनको सत्ता न सौंपकर किसी एक दल को सत्ता सौंप देती है तो कायदे से जनता ने उनको विपक्ष का काम करने को कहा तो वही करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि जिसे जनता सत्ता के लायक नहीं समझती है, वह सरकार से खुद को हर तरह से लायक साबित करने जुट जाता है। उसके लिए सबसे आसान होता है कि सरकार को हर क्षेत्र में फेल बताना।रोज बयान जारी करना होता है, सरकार इस क्षेत्र में फेल है, सरकार उस क्षेत्र में फेल है। इसके लिए वह कोई रचनात्मक काम नहीं करता है। ऐसा काम भी नहीं करता है जो जनता को अच्छा लगे। इसके लिए वह रोज बयान जारी करने के साथ ही हर तीन चार माह में शक्ति प्रदर्शन करता है। यह जानते हुए भी शक्ति प्रदर्शन करता है कि उससे न तो राज्य को फायदा होना है और न ही जनता को कोई फायदा होना है। शक्ति प्रदर्शन से जनता को कई दिन तक परेशानी होती है।

अगर राज्य में विधानसभा सत्र चल रहा हो तो विपक्ष की कोशिश तो यही होती है कि विधानसभा घेराव कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जाए। ऐसा नहीं है कि विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरना जरूरी है। विधानसभा सत्र चल रहा है तो हर मुद्दे पर विपक्ष अपनी शक्ति का प्रदर्शन विधानसभा में कर सकता है। विधानसभा में शक्ति प्रदर्शन में वह मजा कहां होता है, जो सड़क पर हजारों लोगों की भीड़ के बीच होता है। ज्यादा भीड़ होती है तो नेताओं को लगता है कि वह वाकई बड़े नेता हैं। पुलिस के साथ घक्ता मुक्की,जोर आजमाइश होने पर ही ऐसा लगता है कि पार्टी के लोगों ने जनता के लिए संघर्ष किया है।जो नेता घायल हो जातै है, उनकी तस्वीरें दूसरे दिन छपती है. यह सबूत होती है कि फलाने नेता ने जनता के लिए अपना खून बहाया था। पार्टी के लिए कितना बड़ा काम किया था। घायल नेताओं की तस्वीर उनके लिए मेडल की तरह होती है।

कोई राजनीतिक दल विधानसभा घेराव करने की घोषणा करता है तो उसके साथ ही पुलिस की तैयारी भी शुरू हो जाती है। राजनीतिक दल जितना बडा होता है, उसके कार्यक्रम में उतनी ही ज्यादा भीड़ जुटती है, इसलिए पुलिस को दल को देखकर अपनी तैयारी करनी पड़ती है। बड़ा राजनीतिक दल है सड़क को एक दो दिन पहले बंद कर दिया जाता है।इससे हजारों लोगों को परेशानी होती है तो होती रहे। विधानसभा घेराव करने वालो को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है.। ज्यादा हुआ तो घेराव करने वाले दल का कोई बड़ा नेता यह बयान दे देगा कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रम से जनता को परेशानी हो। सरकार ने तो हमे मजबूर कर

दिया है घेराव करने के लिए। यानी घेराव कार्यक्रम के दौरान हजारों लोगों को हुई परेशानी के लिए राजनीतिक दल नहीं सरकार जिम्मेदार है।

धरना प्रदर्शन करने वाले,आदोंलन करने वाले सभी राजनीतिक दल जानते है, सभी संगठन भी जानते हैं कि इससे जनता को बहुत परेशानी होती है। लेकिन वह ऐसा कोई रास्ता नहीं निकालते हैं जिससे वह धरना प्रदर्शन भी करे और जनता को कोई परेशानी न हो।कांग्रेस ने 24 जुलाई को विधानसभा को घेराव किया तो शहर की एक सड़क को बंद किया गया। इससे 14 वार्डों की सड़कों व गलियों में जाम लगा रहा। लोग अपने घरों से नहीं निकल सके। ठेला खोमचेवालों को एक दो दिन कमाई नहीं हुई।घेराव को लेकर कांग्रेस नेता का बयान पेपर में पढ़ने को मिला कि लोगों के लिए न्याय मांगने और सरकार को नींद से जगाने के लिए कांग्रेस को विधानसभा का घेराव करना पड़ा।यह बयान पढ़कर जाम से परेशान लोगों ने जरूर यह कहा होगा। हमारे लिए न्याय इस तरह मत मांगो कि हमें परेशानी हो। हमारे लिए न्याय मांगना है तो इस तरह मांगो कि हमें कोई परेशानी न हो।यह किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं है, सभी राजनीतिक दल विपक्ष में रहने पर यही करते हैं। पता नहीं राजनीतिक दलों को कब यह बात समझ में आएगी कि जनता को परेशान कर जनता का विश्वास नहीं जीता जा सकता।

(स्वतंत्र छत्तीसगढ़)

भारत का केंद्रीय बजट 2024-25- मुख्य विशेषताएं...

माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मौजूदा सरकार का पहला बजट पेश किया। बजट में खास तौर पर रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई और मध्यम वर्ग तथा सर्वांगीण समृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बजट में सभी के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने की नौ प्राथमिकताओं का भी विवरण दिया गया है और विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए आवश्यक विशिष्ट कार्यों और सुधारों का सुझाव दिया गया है।

रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित करें।

2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधान मंत्री पैकेज की घोषणा। शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।

बजट प्राथमिकताएं

अंतरिम बजट में निर्धारित विकसित भारत रणनीति के अनुरूप, बजट में सभी के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए निम्नलिखित 9 प्राथमिकताओं पर निरंतर प्रयास की परिकल्पना की गई है।

- कृषि में उत्पादकता और लचीलापन
- रोजगार एवं कौशल
- समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
- विनिर्माण और सेवाएँ
- शहरी विकास
- ऊर्जा सुरक्षा
- आधारभूत संरचना
- नवाचार, अनुसंधान एवं विकास और
- अगली पीढ़ी के सुधार
- आगामी बजट इन पर आधारित होंगे तथा अधिक प्राथमिकताएं और कार्य शामिल किए जाएंगे।

प्राथमिकता 1- कृषि में उत्पादकता और लचीलापन

- कृषि अनुसंधान में परिवर्तन

उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु-अनुकूल किस्मों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की जाएगी। निजी क्षेत्र सहित चुनौती मोड में वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा। सरकार और बाहर के दोनों डोमेन विशेषज्ञ इस तरह के अनुसंधान के संचालन की देखरेख करेंगे।

नई किस्मों का विमोचन

किसानों द्वारा खेती के लिए 32 खेत और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च उपज वाली और जलवायु-लचीली किस्में जारी की जाएंगी।

प्राकृतिक खेती

अगले दो वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती की शुरुआत कराई जाएगी, जिसके लिए उन्हें प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग की सुविधा दी जाएगी। इसका क्रियान्वयन वैज्ञानिक संस्थानों और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा।

- 10,000 आवश्यकता-आधारित जैव-इनपुट संसाधन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

दलहन और तिलहन के लिए मिशन

- आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत किया जाएगा।
- सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने की रणनीति विकसित की जा रही है ।

सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला

- सब्जी उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर क्लस्टर प्रमुख उपभोग केंद्रों के करीब विकसित किए जाएंगे।
- संग्रहण, भंडारण और विपणन सहित सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए किसान-उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा दिया जाएगा।

कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना

- सरकार, राज्यों के साथ साझेदारी में, 3 वर्षों में किसानों और उनकी भूमि को कवर करने के लिए कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगी।
- इस वर्ष के दौरान, डीपीआई का उपयोग करके खरीफ के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण 400 जिलों में किया जाएगा। 6 करोड़ किसानों और उनकी भूमि का विवरण किसान और भूमि रजिस्ट्री में लाया जाएगा। इसके अलावा, 5 राज्यों में जनसमर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की सुविधा दी जाएगी।

झींगा उत्पादन और निर्यात

- झींगा ब्रूडस्टॉक्स के लिए न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटरों का नेटवर्क स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। झींगा पालन, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए वित्तपोषण नाबार्ड के माध्यम से सुगम बनाया जाएगा ।

राष्ट्रीय सहयोग नीति

- ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास और रोजगार सृजन के अवसरों को तीव्र गति से बढ़ाने के लिए सहकारी क्षेत्र के व्यवस्थित, सुव्यवस्थित और सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति का मसौदा तैयार किया जाएगा।
- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं।

प्राथमिकता 2- रोजगार और कौशल

रोजगार से जुड़ा प्रोत्साहन- प्रधानमंत्री पैकेज के एक भाग के रूप में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन के लिए तीन योजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी

योजना ए- पहली बार काम करने वाले

सभी औपचारिक क्षेत्रों में कार्यबल में प्रवेश करने वाले सभी नए व्यक्तियों को एक महीने का वेतन (15,000 रुपये तक) प्रदान करना। पात्रता सीमा प्रति माह 1 लाख रुपये का वेतन होगी ।

योजना बी- विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन- विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करना, जो पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को रोजगार से जुड़ा होगा।

योजना सी- नियोक्ताओं को सहायता - सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को कवर करने के लिए। सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए ईपीएफओ अंशदान के लिए नियोक्ताओं को 2 वर्षों तक 3,000 रुपये प्रति माह तक की प्रतिपूर्ति करेगी।

कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी- उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। साझेदारी में महिलाओं के लिए विशेष कौशल कार्यक्रम आयोजित करने और महिला स्वयं सहायता समूहों के उद्यमों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया जाएगा।

कौशल कार्यक्रम - राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से कौशल विकास के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से-

- 5 वर्ष की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा
- 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को परिणामोन्मुखीकरण के साथ हब और स्पोक व्यवस्था में उन्नत किया जाएगा
- पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु और डिजाइन को उद्योग की मांग के अनुरूप बनाया जाएगा तथा उभरती जरूरतों के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

कौशल ऋण

मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा, ताकि सरकारी प्रवर्तित निधि से गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा सके, जिससे हर साल 25,000 छात्र लाभान्वित होंगे।

शिक्षा ऋण- सरकारी योजनाओं और नीतियों के तहत किसी भी लाभ के अंतर्गत नहीं आने वाले युवाओं की मदद के लिए, घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

प्राथमिकता 3- समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय

सामाजिक न्याय को व्यापक रूप से प्राप्त करने के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सभी पात्र लोगों को कवर करने का संतृप्ति दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। शिल्पकारों, कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों तथा स्ट्रीट वेंडरों की आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने वाली योजनाओं को मजबूत किया जाएगा।

पूर्वोदय- बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश समेत पूर्वी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए एक योजना तैयार की जाएगी। इस योजना में मानव संसाधन, बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक अवसरों के सृजन को शामिल किया जाएगा। अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर पर, जो पूर्वी क्षेत्र के औद्योगिक विकास को गति देगा, गया में एक औद्योगिक नोड विकसित किया जाएगा। बिहार

में सड़क सम्पर्क और बिजली परियोजनाओं के विकास को समर्थन दिया जाएगा तथा नए हवाई अड्डों, मेडिकल कॉलेजों और खेल अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा।

महिलाओं के नेतृत्व में विकास- महिला-नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए, बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है।

प्राथमिकता 4- विनिर्माण और सेवाएँ

एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए समर्थन- एमएसएमई और विनिर्माण, विशेष रूप से श्रम-प्रधान विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने एमएसएमई के लिए वित्तपोषण, विनियामक परिवर्तन और प्रौद्योगिकी सहायता को शामिल करते हुए एक पैकेज तैयार किया है। निम्नलिखित विशिष्ट उपायों की घोषणा की गई-

विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना- एमएसएमई को मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए बिना किसी जमानत या तीसरे पक्ष की गारंटी के टर्म लोन की सुविधा देने के लिए, एक क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की जाएगी। यह योजना ऐसे एमएसएमई के क्रेडिट जोखिमों को मिलाकर संचालित होगी। एक अलग से गठित स्व-वित्तपोषण गारंटी निधि प्रत्येक आवेदक को 100 करोड़ रुपये तक की गारंटी प्रदान करेगी, जबकि ऋण राशि इससे अधिक हो सकती है।

एमएसएमई ऋण के लिए नया मूल्यांकन मॉडल- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बाहरी मूल्यांकन पर निर्भर रहने के बजाय एमएसएमई को ऋण देने के लिए अपनी आंतरिक क्षमता का निर्माण करेंगे। वे अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के डिजिटल पदचिह्नों के स्कोरिंग के आधार पर एक नया ऋण मूल्यांकन मॉडल विकसित करने या विकसित करवाने में भी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। यह केवल परिसंपत्ति या टर्नओवर मानदंड के आधार पर ऋण पात्रता के पारंपरिक मूल्यांकन की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार होने की उम्मीद है। यह औपचारिक लेखा प्रणाली के बिना एमएसएमई को भी कवर करेगा।

तनाव की अवधि के दौरान एमएसएमई को ऋण सहायता- एमएसएमई को उनके तनाव की अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा की गई। अपने नियंत्रण से परे कारणों से विशेष उल्लेख खाते (एसएमए) चरण में होने के दौरान, एमएसएमई को अपना व्यवसाय जारी रखने और एनपीए चरण में जाने से बचने के लिए ऋण तक पहुंच होगी। सरकार द्वारा प्रवर्तित निधि से गारंटी के माध्यम से ऋण उपलब्धता का समर्थन किया जाएगा।

मुद्रा ऋण- उन उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी जाएगी, जिन्होंने तरुण श्रेणी के अंतर्गत पिछले ऋण लिए हैं और सफलतापूर्वक चुका दिए हैं। ञत्रद्धष्ठस में अनिवार्य ऑनबोर्डिंग का दायरा बढ़ाया गया 7 ञत्रद्धष्ठस प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए खरीदारों की टर्नओवर सीमा को घटाकर 250 करोड़ रुपये किया जाना है। इससे एमएसएमई को अपने व्यापार प्राप्तियों को नकदी में परिवर्तित करके अपनी कार्यशील पूंजी अनलॉक करने में मदद मिलेगी। इस उपाय से 22 और CPSE और 7000 और कंपनियाँ प्लेटफॉर्म पर आ जाएँगी। आपूर्तिकर्ताओं के दायरे में मध्यम उद्यमों को भी शामिल किया जाएगा।

एमएसएमई क्लस्टरों में सिडबी शाखाएँ- सिडबी अपनी पहुंच का विस्तार करने के लिए तीन साल के भीतर सभी प्रमुख एमएसएमई क्लस्टरों तक अपनी सेवाएं पहुंचाने और उन्हें सीधे ऋण उपलब्ध कराने के लिए नई शाखाएं खोलेगा। इस साल ऐसी 24 शाखाएं खुलने के साथ ही सेवा कवरेज 242 प्रमुख क्लस्टरों में से 168 तक विस्तारित हो जाएगी।

खाद्य विकिरण, गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए एमएसएमई इकाइयाँ- एमएसएमई क्षेत्र में 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। एनएबीएल मान्यता प्राप्त 100 खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना में सहायता की जाएगी।

ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र- एमएसएमई और पारंपरिक कारीगरों को अपने उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेचने में सक्षम बनाने के लिए पीपीपी मोड में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। निर्बाध विनियामक और लॉजिस्टिक ढांचे के तहत ये केंद्र एक ही छत के नीचे व्यापार और निर्यात से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे।

विनिर्माण एवं सेवाओं को बढ़ावा देने के उपाय

औद्योगिक पार्क

- नगर नियोजन योजनाओं का बेहतर उपयोग करके, राज्यों और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में, 100 शहरों में या उसके निकट सम्पूर्ण अवसंरचना के साथ निवेश के लिए तैयार प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्कों का विकास।
- राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बारह औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जानी है।

किराये का आवास

- औद्योगिक श्रमिकों के लिए छात्रावास-प्रकार के आवास के साथ किराये के आवास को वीजीएफ समर्थन और प्रमुख उद्योगों की प्रतिबद्धता के साथ पीपीपी मोड में सुगम बनाया जाएगा।

नौवहन उद्योग

- भारतीय शिपिंग उद्योग की हिस्सेदारी बढ़ाने तथा अधिक रोजगार सृजन के लिए स्वामित्व, पट्टा और ध्वज निर्धारण संबंधी सुधार लागू किए जाएंगे।

महत्वपूर्ण खनिज मिशन

घरेलू उत्पादन, महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण और महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों के विदेशी अधिग्रहण के लिए। इसके अधिदेश में प्रौद्योगिकी विकास, कुशल कार्यबल, विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी ढांचा और उपयुक्त वित्तपोषण तंत्र शामिल होंगे।

खनिजों का अपतटीय खनन

खनन के लिए अपतटीय ब्लॉकों की पहली खेप की नीलामी, जो पहले से किए गए अन्वेषण पर आधारित होगी।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना अनुप्रयोग

उत्पादकता लाभ, व्यावसायिक अवसरों और निजी क्षेत्र द्वारा नवाचार के लिए जनसंख्या स्तर पर DPI अनुप्रयोगों का विकास। ये ऋण, ई-कॉमर्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून और न्याय, रसद, एमएसएमई, सेवा वितरण और शहरी शासन के क्षेत्रों में योजनाबद्ध हैं।

आईबीसी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच

दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत परिणामों में सुधार लाने के लिए एक एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच स्थापित किया जाएगा, ताकि सभी हितधारकों के लिए स्थिरता, पारदर्शिता, समय पर प्रसंस्करण और बेहतर निगरानी प्राप्त की जा सके।

एलएलपी का स्वैच्छिक बंद होना

एलएलपी को स्वैच्छिक रूप से बंद करने के लिए सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलेरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट (सी-पेस) की सेवाओं का विस्तार किया जाएगा, ताकि बंद होने का समय कम किया जा सके।

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण

दिवालियेपन के समाधान में तेजी लाने के लिए ढ्क्ष्ट में उचित बदलाव, न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरणों में सुधार और मजबूती की पहल की जाएगी। अतिरिक्त न्यायाधिकरण स्थापित किए जाएंगे। उनमें से कुछ को विशेष रूप से कंपनी अधिनियम के तहत मामलों का फैसला करने के लिए अधिसूचित किया जाएगा।

ऋण वसूली

ऋण वसूली न्यायाधिकरणों में सुधार और उन्हें मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। वसूली में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त न्यायाधिकरणों की स्थापना की जाएगी।

प्राथमिकता 5- शहरी विकास

विकास केन्द्र के रूप में शहर

राज्यों के साथ मिलकर काम करते हुए सरकार शहरों को ग्रोथ हब के रूप में विकसित करने में मदद करेगी। यह आर्थिक और पारगमन नियोजन तथा शहरी नियोजन योजनाओं का उपयोग करके पेरी-अर्बन क्षेत्रों के व्यवस्थित विकास के माध्यम से हासिल किया जाएगा।

शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास

परिवर्तनकारी प्रभाव के साथ मौजूदा शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास के लिए सरकार सक्षम नीतियों, बाजार आधारित तंत्र और विनियमन के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगी।

पारगमन उन्मुख विकास

30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए पारगमन उन्मुख विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी, साथ ही कार्यान्वयन और वित्तपोषण रणनीति भी बनाई जाएगी।

शहरी आवास

पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। इसमें अगले 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल होगी।

बेहतर उपलब्धता के साथ कुशल और पारदर्शी किराया आवास बाजार के लिए सक्षम नीतियां और विनियमन भी लागू किए जाएंगे।

जल आपूर्ति एवं स्वच्छता

राज्य सरकारों और बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ साझेदारी में, बैंक योग्य परियोजनाओं के माध्यम से 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं और सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। इन परियोजनाओं में सिंचाई और आस-पास के क्षेत्रों में टैंकों को भरने के लिए उपचारित पानी के उपयोग की भी परिकल्पना की गई है।

प्राथमिकता 6- ऊर्जा सुरक्षा

ऊर्जा संक्रमण

उचित ऊर्जा संक्रमण पथ पर एक नीति दस्तावेज तैयार किया जाएगा जो रोजगार, विकास और पर्यावरणीय स्थिरता की अनिवार्यताओं को संतुलित करेगा।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को 1.28 करोड़ से अधिक पंजीकरण और 14 लाख आवेदनों के साथ उल्लेखनीय प्रतिक्रिया मिली है और सरकार इसे और प्रोत्साहित करेगी।

पंप स्टोरेज नीति

- विद्युत भंडारण के लिए पम्प भंडारण परियोजनाओं को बढ़ावा देने तथा समग्र ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी को उसकी परिवर्तनशील एवं अस्थायी प्रकृति के साथ सुचारू रूप से एकीकृत करने के लिए एक नीति तैयार की जाएगी।
- छोटे और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों का अनुसंधान और विकास
- उम्मीद है कि परमाणु ऊर्जा, विकसित भारत के ऊर्जा मिश्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगी।
- सरकार भारत लघु रिएक्टरों की स्थापना, भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान एवं विकास तथा परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी।

उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट

उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (AUSC) थर्मल पावर प्लांट के लिए स्वदेशी तकनीक का विकास बहुत अधिक दक्षता के साथ पूरा हो गया है। हृज्ञक्ष्ट और क्ष्ाश्वरु के बीच एक संयुक्त उद्यम् स्ष्ट तकनीक का उपयोग करके एक पूर्ण पैमाने पर 800 मेगावाट वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करेगा। सरकार आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। आगे बढ़ते हुए, इन संयंत्रों के लिए उच्च श्रेणी के स्टील और अन्य उन्नत धातुकर्म सामग्री के उत्पादन के लिए स्वदेशी क्षमता के विकास से अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत स्पिन-ऑफ लाभ होंगे।

कठिन निवारण उद्योगों के लिए रोडमैप

ऊर्जा दक्षता लक्ष्यों से उत्सर्जन लक्ष्यों की ओर कठिन उद्योगों को ले जाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया जाएगा। इन उद्योगों को वर्तमान %प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार% मोड से %भारतीय कार्बन बाजार% मोड में बदलने के लिए उचित नियम बनाए जाएंगे।

पारंपरिक सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को समर्थन

पीतल और सिरेमिक सहित 60 क्लस्टरों में पारंपरिक सूक्ष्म और लघु उद्योगों का निवेश-ग्रेड ऊर्जा ऑडिट किया जाएगा। उन्हें स्वच्छ ऊर्जा के रूपों में स्थानांतरित करने और ऊर्जा दक्षता उपायों के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगले चरण में इस योजना को अन्य 100 क्लस्टरों में दोहराया जाएगा।

प्राथमिकता 7- बुनियादी ढांचा

केन्द्र सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे में निवेश

अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे के लिए मजबूत राजकोषीय सहायता जारी रहेगी, साथ ही अन्य प्राथमिकताओं और राजकोषीय समेकन की अनिवार्यताएं भी जारी रहेंगी। इस वर्ष, पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,111 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 3.4प्रतिशत होगा।

राज्य सरकारों द्वारा बुनियादी ढांचे में निवेश

राज्यों को उनकी विकास प्राथमिकताओं के अधीन, बुनियादी ढांचे के लिए समान पैमाने पर सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्यों को उनके संसाधन आवंटन में सहायता देने के लिए दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बुनियादी ढांचे में निजी निवेश

व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण और सक्षम नीतियों और विनियमों के माध्यम से निजी क्षेत्र द्वारा बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। बाजार आधारित वित्तपोषण ढांचा लाया जाएगा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पीएमजीएसवाई का चरण ढ्ढङ्क शुरू किया जाएगा।

पर्यटन

- भारत को वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के सरकार के प्रयासों से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और अन्य क्षेत्रों के लिए आर्थिक अवसर खुलेंगे। अंतरिम बजट में उल्लिखित उपायों के अलावा, निम्नलिखित उपाय प्रस्तावित किए गए-
- विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर के व्यापक विकास को समर्थन दिया जाएगा ताकि उन्हें विश्व स्तरीय तीर्थ और पर्यटन स्थल में परिवर्तित किया जा सके।

राजगीर का समग्र विकास।

- नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने के अलावा नालंदा को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना।
- ओडिशा के प्राकृतिक सौंदर्य, मंदिरों, स्मारकों, शिल्पकला, वन्यजीव अभयारण्यों, प्राकृतिक परिदृश्यों और प्राचीन समुद्र तटों का विकास करके इसे एक परम पर्यटन स्थल बनाया जाएगा।

प्राथमिकता 8- नवाचार, अनुसंधान और विकास

बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा, 1 लाख करोड़ रुपये के वित्तपोषण पूल के साथ वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा।

अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था

अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने पर सरकार के निरंतर जोर के साथ, 1,000 करोड़ रुपये का उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा।

प्राथमिकता 9- अगली पीढ़ी के सुधार

आर्थिक नीति ढांचा

- आर्थिक विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण को रेखांकित करने तथा रोजगार के अवसरों को सुविधाजनक बनाने और उच्च विकास को बनाए रखने के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों का दायरा निर्धारित करने के लिए एक आर्थिक नीति ढांचा तैयार किया जाएगा।
- सरकार उत्पादन के कारकों की उत्पादकता में सुधार लाने तथा बाजारों और क्षेत्रों को अधिक कुशल बनाने के लिए सुधारों की शुरुआत करेगी और उन्हें प्रोत्साहित करेगी। ये सुधार उत्पादन के सभी कारकों, अर्थात् भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता, तथा प्रौद्योगिकी को कवर करेंगे, जो कुल कारक उत्पादकता में सुधार लाने और असमानता को पाटने में सहायक होंगे।
- प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने और सुधारों के तेजी से क्रियान्वयन के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निर्धारित किया जाएगा। राज्यों के साथ मिलकर निम्नलिखित सुधार शुरू किए जाएंगे-

राज्य सरकारों द्वारा भूमि-संबंधी सुधार

- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमि से संबंधित सुधार और कार्रवाई में भूमि प्रशासन, योजना और प्रबंधन, तथा शहरी नियोजन, उपयोग और भवन उपनियम शामिल होंगे। इन्हें उचित वित्तीय सहायता के माध्यम से अगले 3 वर्षों के भीतर पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- ग्रामीण भूमि से संबंधित कार्यों में शामिल होंगे- सभी भूमि के लिए विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (LPIN) या भू-आधार का आवंटन, कैडस्ट्रल मानचित्रों का डिजिटलीकरण, वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उप-विभाजनों का सर्वेक्षण, भूमि रजिस्ट्री की स्थापना, और किसानों की रजिस्ट्री से लिंक करना। इन कार्यों से ऋण प्रवाह और अन्य कृषि सेवाओं में भी सुविधा होगी।
- शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को जीआईएस मैपिंग के साथ डिजिटल किया जाएगा। संपत्ति अभिलेख प्रशासन, अद्यतनीकरण और कर प्रशासन के लिए आईटी आधारित प्रणाली स्थापित की जाएगी। इससे स्थानीय शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा।

सुधार

- सरकार श्रमिकों को रोजगार और कौशल विकास सहित कई तरह की सेवाएं उपलब्ध कराएगी। ई-श्रम पोर्टल का अन्य पोर्टलों के साथ व्यापक एकीकरण इस तरह के वन-स्टॉप समाधान की सुविधा प्रदान करेगा। तेजी से बदलते श्रम बाजार, कौशल आवश्यकताओं और उपलब्ध नौकरी भूमिकाओं के लिए ओपन आर्किटेक्चर डेटाबेस और नौकरी के इच्छुक लोगों को संभावित नियोक्ताओं और कौशल प्रदाताओं से जोड़ने के लिए एक तंत्र इन सेवाओं में शामिल किया जाएगा।
- उद्योग और व्यापार के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए श्रम सुविधा और समाधान पोर्टलों का नवीनीकरण किया जाएगा।
- अर्थव्यवस्था की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार वित्तीय क्षेत्र के लिए एक विजन और रणनीति दस्तावेज लाएगी, ताकि आकार, क्षमता और कौशल के मामले में क्षेत्र को तैयार किया जा सके। यह अगले 5 वर्षों के लिए एजेंडा तय करेगा और सरकार, नियामकों, वित्तीय संस्थानों और बाजार सहभागियों के काम का मार्गदर्शन करेगा।

जलवायु वित्त के लिए वर्गीकरण

जलवायु अनुकूलन और शमन के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जलवायु वित्त के लिए एक वर्गीकरण विकसित किया जाएगा। इससे देश की जलवायु प्रतिबद्धताओं और हरित परिवर्तन की प्राप्ति में सहायता मिलेगी।

परिवर्तनीय पूंजी कंपनी संरचना

सरकार विमानों और जहाजों के पट्टे के वित्तपोषण के लिए एक कुशल और लचीला तरीका उपलब्ध कराने तथा परिवर्तनशील कंपनी संरचना के माध्यम से निजी इक्विटी के एकत्रित कोष के लिए आवश्यक विधायी अनुमोदन प्राप्त करेगी।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी निवेश

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी निवेश के नियमों और विनियमों को सरल बनाया जाएगा ताकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाया जा सके, प्राथमिकता को बढ़ावा दिया जा सके और विदेशी निवेश के लिए भारतीय रुपये को मुद्रा के रूप में उपयोग करने के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके।

प्रौद्योगिकी का उपयोग

अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण की दिशा में प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना बढ़ाया जाएगा।

व्यापार करने में आसानी

कारोबार में आसानी को बढ़ाने के लिए सरकार पहले से ही जन विश्वास विधेयक 2.0 पर काम कर रही है। इसके अलावा, राज्यों को उनके व्यापार सुधार कार्य योजनाओं और डिजिटलीकरण के कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

डेटा और सांख्यिकी

डेटा शासन, डेटा और सांख्यिकी के संग्रहण, प्रसंस्करण और प्रबंधन में सुधार के लिए, डिजिटल इंडिया मिशन के तहत स्थापित सहित विभिन्न क्षेत्रीय डेटा बेस का उपयोग प्रौद्योगिकी उपकरणों के सक्रिय उपयोग के साथ किया जाएगा।

कर लगाना

अप्रत्यक्ष कर

अगले छह महीनों में दर संरचना की व्यापक समीक्षा से सीमा शुल्क दरों को युक्तिसंगत और सरल बनाया जाएगा, जिससे व्यापार को सुविधाजनक बनाया जा सकेगा, शुल्क व्युत्क्रमण को दूर किया जा सकेगा और विवादों को कम किया जा सकेगा।

क्षेत्र-विशिष्ट सीमा शुल्क प्रस्ताव

दवाइयां और चिकित्सा उपकरण

- तीन और कैंसर दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई।
- चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत मेडिकल एक्स-रे मशीनों में उपयोग के लिए एक्स-रे ट्यूबों और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर बीसीडी में परिवर्तन, ताकि उन्हें घरेलू क्षमता संवर्धन के साथ समन्वयित किया जा सके।

मोबाइल फ़ोन और संबंधित पार्ट्स

मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए और मोबाइल चार्जर पर बीसीडी को घटाकर 15त्न किया गया।

महत्वपूर्ण खनिज

सरकार ने 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क में पूरी तरह छूट देने और उनमें से दो पर बीसीडी कम करने का प्रस्ताव रखा है। इससे ऐसे खनिजों के प्रसंस्करण और शोधन को बढ़ावा मिलेगा और परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा, दूरसंचार और उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे रणनीतिक और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

सौर ऊर्जा

ऊर्जा संक्रमण को समर्थन देने के लिए, देश में सौर सेल और पैनल के निर्माण में उपयोग के लिए छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची का विस्तार किया जाना है। इसके अलावा, सौर ग्लास और टिनड कॉपर इंटरकनेक्ट की पर्याप्त घरेलू विनिर्माण क्षमता को देखते हुए, सरकार ने उन्हें प्रदान की गई सीमा शुल्क छूट को आगे न बढ़ाने का प्रस्ताव दिया।

समुद्री उत्पाद

- प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए, कुछ ब्रूडस्टॉक, पॉलीचेट वर्म्स, झींगा और मछली फ़ीड पर बीसीडी को घटाकर 5प्रतिशत किया जाएगा।
- झींगा और मछली आहार के विनिर्माण के लिए विभिन्न इनपुट पर सीमा शुल्क में छूट ।

चमड़ा और वस्त्र

- निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सरकार ने बत्तख या हंस से प्राप्त वास्तविक डाउन फिलिंग सामग्री पर बीसीडी को कम करने का प्रस्ताव किया है।
- चमड़ा और वस्त्र निर्माण के लिए छूट प्राप्त वस्तुओं, परिधानों, जूतों और अन्य चमड़े की वस्तुओं के निर्यात की सूची का विस्तार किया जाएगा।
- शुल्क में परिवर्तन को सुधारने के लिए, सरकार ने स्पैन्डेक्स यार्न के विनिर्माण के लिए मेथिलीन डाइफेनिल डायइसोसायनेट (एमडीआई) पर बीसीडी को शर्तों के अधीन 7.5प्रतिशत से घटाकर 5प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है।

कच्चे खाल, चमड़े और चमड़े पर निर्यात शुल्क संरचना को सरल और युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव है।

कीमती धातु

देश में सोने और बहुमूल्य धातु के आभूषणों में घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ाने के लिए सोने और चांदी पर सीमा शुल्क को घटाकर 6प्रतिशत तथा प्लैटिनम पर 6.4 प्रतिशत किया गया।

अन्य धातुएं

इस्पात और तांबे के उत्पादन की लागत कम करने के लिए सरकार ने फेरो निकेल और ब्लिस्टर कॉपर पर बीसीडी हटाने का प्रस्ताव रखा है। फेरस स्क्रैप और निकेल कैथोड पर शून्य बीसीडी और तांबे के स्क्रैप पर 2.5 प्रतिशत की रियायती बीसीडी जारी रहेगी।

इलेक्ट्रानिक्स

- घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में मूल्य संवर्धन को बढ़ाने के लिए,
- प्रतिरोधकों के निर्माण के लिए ऑक्सीजन-मुक्त तांबे पर कुछ शर्तों के अधीन बीसीडी को हटाया जाएगा। कनेक्टरों के निर्माण के लिए कुछ भागों को भी छूट दी जाएगी।

रसायन और पेट्रोरसायन

पाइपलाइन में मौजूदा और नई क्षमताओं को समर्थन देने के लिए, अमोनियम नाइट्रेट पर बीसीडी को 7.5 से 10 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा।

प्लास्टिक

पीवीसी फ्लेक्स बैनरों के आयात पर अंकुश लगाने के लिए उन पर बीसीडी को 10 से बढ़ाकर 25प्रतिशत किया जाएगा।

दूरसंचार उपकरण

घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए, निर्दिष्ट दूरसंचार उपकरणों के पीसीबीए पर बीसीडी को 10 से 15प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है।

ट्रेड फ़ैसिलिटेशन

घरेलू विमानन तथा नाव एवं जहाज एमआरओ को बढ़ावा देने के लिए मरम्मत के लिए आयातित माल के निर्यात की अवधि को बढ़ाकर एक वर्ष किया जाएगा।

वारंटी के अंतर्गत मरम्मत के लिए माल के पुनः आयात की समय सीमा तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष की जाएगी।

प्रत्यक्ष कर

निवेश

- भारतीय स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने और नवाचार को समर्थन देने के लिए, सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त किया जाना है।
- रोजगार सृजन उद्योग, क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, देश में घरेलू क्रूज संचालित करने वाली विदेशी शिपिंग कंपनियों के लिए एक सरल कर व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया।
- हीरा कटाई और पॉलिशिंग क्षेत्र के विकास को और बढ़ावा देने के लिए, देश में कच्चे हीरे बेचने वाली विदेशी खनन कंपनियों के लिए सुरक्षित बंदरगाह दरें लागू की जाएंगी।
- भारत की विकास आवश्यकताओं के लिए विदेशी पूंजी आकर्षित करने हेतु
- विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर की दर 40प्रतिशत से घटाकर 35प्रतिशत की जाएगी।

सुविधाओं के नाम पर भारी पड़ रही बैंकों की वसूलियां ...

पिछले पांच सालों में एसबीआई को छोड़ शेष 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने केवल और केवल मिनिमम बैलेंस के नाम पर 8 हजार 500 रु. करोड़ रु. की कमाई की है। इसका साफ साफ अर्थ है कि गरीब आदमी के खातों से साढ़े आठ हजार करोड़ रुपए तो इन बैंकों में न्यूनतम बैलेंस ना रख पाने के कारण गवाने पड़े है। यह तो तब है जब देश के सबसे बड़े बैंक ने 2019-20 में न्यूनतम बैलेंस की पैनेल्टी के रुप में 640 करोड़ जुर्माना के रुप में वसूलने के बाद न्यूनतम बैलेंस पर पेनेल्टी लगाने का आदेश वापिस ले लिया। 12 में से 11 बैंकों की साढ़े 8 हजार करोड़ की पांच साल में पेनेल्टी वसूली रही है तो कल्पना की जा सकती है कि निजी क्षेत्र के बैंकों ने इस तरह के जुर्माने से कितना खजाना भरा होगा। साढ़े 8 हजार करोड़ रु. की जुर्माना राशि का आंकड़ा किसी भी तरह से कपोल कल्पित या अतिशयोक्ति पूर्ण नहीं हैं क्योंकि यह जानकारी अधिकृत रुप से संसद में केन्द्रीय वित राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा दी गई है। एक मोटे अनुमान के अनुसार देश में बैंकों में मार्च, 23 में 294 करोड़ से अधिक खाते हैं। अब यह स्पष्टीकरण देने का कोई मतलब नहीं कि यह पैसा गरीब खातेदारों के अकाउंट्स से ही गया हैं क्योंकि पैसे वाले खाताधारकों के खातों में तो न्यूनतम बैलेंस रहता ही है।

देश में बैंकिंग नेटवर्क का इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 22 निजी क्षेत्र के बैंक, 44 विदेशी बैंक, 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 1485 अरबन कोआपरेटिव बैंक और हजारों की संख्या में ग्रामीण सहकारी बैंकिंग संस्थाएं हैं। यह तो सभी संस्थागत बैंकिंग संस्थाएं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बैंकिंग सेवाओं का विस्तार हुआ है। 24 गुणा 7 सेवाएं मिलने लगी है। जन धन खातों की परिकल्पना से गरीब से गरीब आदमी का बैंकों से जुड़ाव हुआ है। और अब डिजिटल लेन-देन की सुविधा ने तो सब कुछ ही बदल कर रख दिया है। आज पांच रुपए का धनिया तक पेटीएम या इसी तरह के किसी प्लेटफार्म से आसानी से भुगतान कर खरीदा जा सकता है। दिन प्रतिदिन डिजिटल पेमेंट का चलन आम होता जा रहा है। चंद मिनटों में कहीं से भी किसी को भी मोबाइल या ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा से चंद सैकंड में भुगतान पहुंचने लगा है। यह सब बैंकिंग सेवाओं में सुधार और विस्तार का उदाहरण है तो दूसरी और नकदी लेन-देन का स्थान डिजिटल पेमेंट ने ले लिया है।

बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार निष्चित रुप से शुभ संकेत माना जाना चाहिए। यह भी साफ है कि लोगों में निश्चित रुप से अवेयरनेस आई है। यह दूसरी बात है कि साइबर ठगी के मामलें भी बहुत अधिक होने लगे हैं। पर सबसे अधिक चिंतनीय बैंकों द्वारा अपनी आय बढ़ाने के लिए सुविधाओं के नाम पर चार्जेज लगालगाकर अपनी आय बढ़ाना है। आम आदमी को किसी तरह की गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि बैंक उन्हें यह सेवाएं फ्री में दे रहे हैं। आज हालात यह है कि एटीएम पोस मशीन से बड़ा बड़ा कारोबारी भुगतान लेने को तैयार नहीं होता। उसका साफ कहना होता है कि इसमें हमारे चार्जेज लग जाते हैं इसलिए डिजिटल प्लेटफार्म से ही भुगतान प्राप्त करना उचित समझते हैं। खैर चिंतनीय बात

यह है कि बैंकों द्वारा सुविधाओं के नाम पर वसूली राशि बहुत अधिक होने के साथ ही आम खाताधारक के लिए भारी पड़ने लगी है। आज हो यह रहा है कि बैंक की छोटी से छोटी सेवा के लिए भी भुगतान करना पड़ता है। भुगतान के आसान तरीके आरटीजीएस और एनईएफटी की सेवाएं चार्जेवल है।

हांलाकि दो लाख तक के आरटीजीएस पर कोई चार्ज नहीं लिया जाता पर राशि बढ़ने के साथ ही चार्ज बढ़ता जाता है। डुप्लीकेट पासबुक से लेकर चैक बाउंस होने पर रिटर्न चार्ज, सिग्नेचर वैरीफाई चार्ज, नोमिनी का नाम बदलवाने, इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट लेने, ईकेवाईसी और इसी तरह की सेवाओं के लिए चार्ज लिए जाते हैं। एटीएम का उपयोग हांलाकि अब कम होता जा रहा है पर दूसरे बैंक के एटीएम के उपयोग और इसी तरह की अन्य सेवाओं के लिए चार्जेज आम होता जा रहा है। देखा जाए तो हमें पता ही नहीं चल पाता कि बैंकों द्वार कब कितना पैसा काट लिया जाता है।

लेनदेन की सूचना के एसएमएस से लेकर अन्य सेवाएं करीब करीब सषुल्क होने के कारण हमें कुछ ना कुछ चुकाना ही पड़ता है। चिंतनीय यह है कि इस सबके बावजूद बैंकों में ग्राहकों के प्रति जो संवेदनशीलता और आपसी संबंध होने चाहिए वह कहीं खोते जा रहे हैं।

इसमें कोई दो राय नहीं कि बैंक सेवा प्रदाता संस्था हैं और सहज सुविधाएं उपलब्ध कराने और निरंतर सेवाओं में सुधार के लिए बैंकों द्वारा प्रयास किये जाते रहे हैं। पर इसके साथ ही बैंकों को न्यूनतम बैलेंस या अन्य तरह के अनावश्यक चार्जेज लगाने से पहले आम खाताधारकों के हितों को भी देखना चाहिए। बैंक केवल और केवल पैसा कमाने का स्थान नहीं हैं अपितु बैंकों की भी आमजन के प्रति जिम्मेदारी बनती हैं। सभी कुछ केचल और केचल खाताधारक से ही देय है तो फिर बैंकों और पुराने जमाने के साहूकारों या आज के गली गली में फैले सूदखोरों या फिर बॉक्सरों से वसूली करने वाली संस्थाओं से अलग होना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं सरकार और बैंकिंग संस्थाओं को जनसरोकारों से भी जुड़ना होगा ताकि जिस तरह से पिछले कुछ सालों में बैंकों में आम आदमी की सहज पहुंच हुई हैं और आमआदमी का मोबाईल अब बैंक बन गया है यह सराहनीय है। आवश्यकता चार्जेज के पुनरावलोकन की है। इस और ध्यान देना ही होगा।

गेड़ी बिना अधूरा है हरेली तिहार...

हरेली छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है। प्रदेश में इस त्यौहार का विशेष महत्व है। लोग त्यौहार को परंपरागत रूप से बड़े ही उत्साह के साथ मानते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गेड़ी के बिना हरेली तिहार अधूरा है। सावन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरेली पर्व मनाया जाता है। हरेली का आशय हरियाली ही है। वर्षा ऋतु में धरती हरा चादर ओढ़ लेती है। वातावरण चारों ओर हरा-भरा नजर आने लगता है। हरेली तिहार के साथ गेड़ी चढ़ने की परंपरा अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग सभी घरों गेड़ी का बनाया जाता है। परिवार के बच्चे और युवा गेड़ी का जमकर आनंद लेते है। गेड़ी बांस से बनाई जाती है।

गेड़ी पर चलते समय रच-रच की ध्वनि निकलती हैं, जो वातावरण को और आनंददायक बना देती है। इसके साथ ही शाम को युवा वर्ग, बच्चे गांव के गली में नारियल फेंक और गांव के मैदान में कबड्डी आदि कई तरह के खेल खेलते हैं। बहु-बेटियां नए वस्त्र धारण कर सावन झूला, बिल्लस, खो-खो, फुगड़ी आदि खेल का आनंद लेती हैं। छत्तीसगढ़ के गांव में अक्सर हरेली तिहार के पहले ही गेड़ी घरों में बनना शुरू हो जाता है। त्यौहार के दिन सुबह से ही तालाब के पनघट में किसान परिवार, बड़े बजुर्ग बच्चे सभी अपने गाय, बैल, बछड़े को नहलाते हैं। साथ ही खेती-किसानी, औजार, हल (नांगर), कुदाली, फावड़ा, गैंती को धोते हैं। इसके अलावा घर के आंगन में मुरूम बिछाकर पूजा के लिए सजाते हैं। माताएं गुड़ का चीला बनाती हैं। कृषि औजारों को धूप-दीप से पूजा के बाद नारियल, गुड़ के चीला का भोग लगाया जाता है। अपने-अपने घरों में अराध्य देवी-देवताओं के साथ पूजा करते हैं। गांवों के ठाकुरदेव की पूजा की जाती है।

गेड़ी की पूजा भी की जाती है

हरेली के दिन बच्चे बांस से बनी गेड़ी का आनंद लेते हैं। पहले के दशक में गांव में बारिश के समय कीचड़ आदि हो जाता था उस समय गेड़ी से गली का भ्रमण करने का अपना अलग ही आनंद होता है। गांव-गांव में गली कांक्रीटीकरण से अब कीचड़ की समस्या काफी हद तक दूर हो गई है। हरेली के दिन गृहणियां अपने चूल्हे-चौके में कई प्रकार के छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाती है

अग्नीवीरों के लिए रोजगार की व्यवस्था ,भाजपा सरकार का सराहनीय कदम ...

(राखी श्रीवास्तव)

देश व राज्य के कुछ मामले राजनीति से परे होते हैं,कम से कम उस पर तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। देश की सुरक्षा, सेना में सुधार, सेना को मजबूत करने का प्रयास कोई भी सरकार कर रही है विपक्ष को उसमें खुले मन से सहयोग करना चाहिए क्योंकि सेना किसी दल की नहीं होती है, वह देश की होती है।वह मजबूत होगी तो देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी।देश मे पहली बार विपक्ष सेना के सुधार के मामले में राजनीति कर रहा है ताकि कोई सुधार का काम मोदी सरकार कर रही है तो उसे हर कीमत पर गलत कहना है और देश के लोगों तथा युवाओं को गुमराह करना है।

सरकार की तरफ से कई बार कहा जा चुका है तथा कारगिल विजय दिवस पर पीएम मोदी ने फिर एक बार कहा है कि अग्निपथ योजना का मकसद देश की सेनाओं को युवा व हरदम युध्द के लिए तैयार रखना है।उन्होंने इस योजना का विरोध करनेवाले को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि अग्निपथ योजना व एयरफोर्स मे फाइटर विमान का विरोध करने वाले वही लोग हैं, जिन्होंने रक्षा सौदे मे हजारों करोड़ के घोटाले कर सेना को कमजोर बनाए रखा है।अतीत में हमेशा सेना में सुधार के नजरअंदाज किया है।उनका कहना है कि अग्निपथ योजना रक्षा के क्षेत्र में बरसों बाद किया जा रहा अहम सुधार कार्य है। इससे सेना की औसत आयु कम होगी तथा हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहेगी और दुश्मन को ठीक समय पर मुंहतोड़ जवाब दे सकेगी।

सेना का मतलब होता है कि जब भी दुश्मन देशों से युध्द हो तो उसका मुकाबला ठीक से किया जा सके और उसे हराया भी जा सके। सेना तो जीतने वाली होनी चाहिए।सेना अतीत में जब भी भारत पर हमला हुआ है तो सेना युध्द के लिए तैयार नहीं थी,इसलिए भारत को नुकसान हुआ है। माना जाता है कि सेना हमेशा युध्द के लिए तैयार रहे तो वह युध्द जीतती है और उसे किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। कहा जाता है कि कारगिल युध्द के बाद से ही सेना महसूस कर रही थी कि सेना की औसत आयु कम करने की जरूरत है यानी सेना में ज्यादा युवाओं की जरूरत है।

कारगिल युध्द के बाद जितनी सरकारे हुई उनमें से शायद की किसी सरकार ने सेना में सुधार की जरूरत को समझा और सुधार किया।सेना की मजबूती के लिए विश्वस्तर पर जो सुधार सभी देशों में होते है, देश की सेना की मजबूती के लिए भी सुधार समय समय पर होते रहने चाहिए। जो सुधार कार्य कई सरकारों ने नहीं किया वह काम मोदी सरकार कर रही है तो उसकी सराहना होनी चाहिए तो विरोध हो रहा है। विरोध करने वाले भी गजब के हैं। वह अग्निपथ योजना को देश के युवाओं के सामने नौकरी देने वाली योजना के रूप में पेश कर रहे हैं। कांग्रेस सहित विपक्ष देश के युवाओं को यह बता रहे हैं कि इससे तुमको क्या नुकसान होगा। मोदी सरकार बता रही है कि इससे देश की सेना को क्या फायदा होगा।

अग्निपथ योजना में साल में दो बार सेना में भर्ती की जाती है।उनको चार साल प्रशिक्षण दिया जाता है।उसके बाद उनको रेटिंग दी जाती है।इसमें मेरिट में आने वाले 25 प्रतिशत जवानों को सेना में लिया जाता है। बाकी की सेवाएं खत्म कर दी जाती हैं।इसी आधार पर राहुल गांधी कहते हैं कि यह योजना यूज एंड थ्रो है। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे कहते हैं कि इस योजना के तहत अग्निवीरों को कुछ नहीं मिलता है,न तो उनको जवानों की तरह पेंशन मिलती है,ने ग्रेच्यूटी, न पारिवारिक पेंशन , उदारीकृत पारिवारिक पेंशन,न ही उनके बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता दिया जाता है। कांग्रेस का कहना है कि इस योजना को बंद कर दिया जाना चाहिए।

कांग्रेस और विपक्ष मोदी सरकार की तरह देश व जनता के हित में कोई अच्छी योजना बना नहीं पाते हैं तो वह पीएम मोदी जो योजना जनता व देशहित में लाते हैं, उसका विरोध करने लगते हैं। उसमें मीनमेख निकालने लगते हैं। उसे देश व जनता के लिए नुकसानदेह बताते हैं। मोदी सरकार ने किसानों के लिए कानून बनाकर कृषि क्षेत्र में सुधार का प्रयास किया था तो कांग्रेस सहित विपक्ष ने उसका भी विरोध किया था। उसे वापस लेने की मांग को लेकर कुछ राज्यों के किसानों को भड़का कर आंदोलन करने प्रेरित किया था। किसानों के आंदोलन के कारण बाद में सरकार को कृषि कानूनों को वापस ले लिया था। अब कांग्रेस चौतरफा दबाव बनाकर अग्निपथ योजना को बंद कराना चाहती है। सरकार इस योजना को वापस लेती है तो यह कांग्रेस की एक और जीत होगी। साथ ही कांग्रेस यह साबित करने में भी सफल हो जाएगी कि मोदी सरकार कमजोर सरकार है।

इस बार सरकार कदम पीछ खींचने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जिन अग्निवीरों को सेना में नहीं लिया जाएगा। सेना से लौटने के बाद उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। पांच राज्य सरकारों यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ,गुजरात व ओडिशा की सरकारों ने घोषणा की है उसके यहां पुलिस,अर्धसैनिक बल,वन विभाग,जेल प्रहरी आदि की नौकरी में उनको आरक्षण दिया जाएगा। यानी भाजपा सरकारों ने अग्निवीरों की यह चिंता दूर कर दी है कि चार साल वह घर वापस आएंगे तो वह क्या करेंगे। ऐसा करके भाजपा सरकारों ने राहुल गांधी व कांग्रेस के हाथ से एक और मुद्दा छीन लिया है। यानी भाजपा सरकार अग्निवीरों को प्रशिक्षण देकर सेना में नौकरी का मौका देगी और वहां मौका न मिलने पर दूसरे विभागों मे मौका दिया जाएगा। इस तरह भाजपा ने कांग्रेस के एक और मुद्दे को राजनीतिक रूप से निष्प्रभावी कर दिया है। इससे अब कांग्रेस के झूठ के कारण जो राजनीतिक नुकसान होता अब नहीं होगा।

किसानों की खुशहाली और समृद्धि हमारा ध्येय- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री निवास में हरेली पर्व पर रंगारंग आयोजन

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि किसानों की खुशहाली और समृद्धि हमारी सरकार का लक्ष्य है। हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है, यहां की 80 प्रतिशत आबादी का जीवन-यापन कृषि पर निर्भर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेकर खेती-किसानी को समृद्ध बनाने का काम किया है। मुख्यमंत्री निवास में हरेली पर्व पर रंगारंग आयोजन मुख्यमंत्री साय आज राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास में आयोजित हरेली तिहार कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर प्रदेशवासियों को हरेली पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 15 साल डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए काम किया है। किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण जैसी सुविधाएं सुलभ करायी गई। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के किसानों को प्रति क्विंटल 3100 रूपए का मूल्य मिल रहा है, जो देश में सर्वाधिक है।

मुख्यमंत्री निवास में हरेली पर्व पर रंगारंग आयोजन हुआ। पूरे परिसर को ग्रामीण परिवेश में सजाया गया था। छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति के पहले पर्व ÷हरेली÷ पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अपनी धर्मपत्नि श्रीमती कौशल्या देवी साय के साथ गौरी-गणेश पूजा कर भगवान शिव का अभिषेक किया। मुख्यमंत्री ने कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले नांगर, रापा, कुदाल व कृषि यंत्रों की विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली एवं सुख-समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय पूरी प्रतिबद्धता और सच्चे मन से प्रदेशवासियों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, फलस्वरूप ईश्वर का आशीर्वाद भी मिल रहा है। प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है। उन्होंने कहा कि बीते छह माह में श्री साय के नेतृत्व में किसानों के कल्याण के लिए बड़े काम किए गए है, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। इस अवसर पर मंत्री श्री टंक राम वर्मा, विधायक सुश्री लता उसेंडी, श्री मोती लाल साहू, श्री अनुज शर्मा, श्री संपत अग्रवाल, श्री गजेन्द्र यादव, श्री खुशवंत साहेब अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री निवास में राउत नाचा और गेड़ी धूम- छत्तीसगढ़ी संगीत, लोकनृत्य, पारंपरिक गड़वा बाजा, राउत नाचा, गेड़ी नृत्य, रहचुली और विभिन्न छत्तीसगढ़ी पकवानों और व्यंजनों के आनंद के साथ मुख्यमंत्री निवास में मौजूद लोग उत्साह के साथ हरेली में शामिल हुए। इस अवसर पर लोक कलाकारों ने राउत नाचा, करमा नृत्य, बस्तरिया नृत्य और गेड़ी चढ़कर नृत्य की प्रस्तुति दी। राउत नाचा के कलाकारों के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ी पारंपरिक वेशभूषा धारण कर कलाकारों का उत्साह बढ़ाया।

अपनो को करीब रखने के लिए कभी कभी अपना हक भी छोड़ना पड़ता है..

(राखी श्रीवास्तव)

विनोद हाईवे पर गाड़ी चला रहा था...

सड़क के किनारे उसे एक 12-13 साल की लड़की तरबूज बेचती दिखाई दी...

विनोद ने गाड़ी रोक कर पूछा तरबूज की क्या रेट है बेटा ?

लड़की बोली

50 रुपये का एक तरबूज है साहब...

पीछे की सीट पर बैठी विनोद की पत्नी बोली

इतना महंगा तरबूज नही लेना जी...चलो यहाँ से...

विनोद बोला महंगा कहाँ है... इसके पास जितने तरबूज है कोई भी पांच किलो के कम का नही होगा... 50 रुपये का एक दे रही है तो 10 रुपये किलो पड़ेगा हमें... बाजार से तो तू बीस रुपये किलो भी ले आती है...

विनोद की पत्नी ने कहा तुम रुको मुझे मोल भाव करने दो...

फिर वह लड़की से बोली 30 रुपये का एक देना है तो दो वरना रहने दो...

लड़की बोली 40 रुपये का एक तरबूज तो मै खरीद कर लाती हूँ आंटी...आप 45 रुपये का एक ले लो...इससे सस्ता मै नही दे पाऊँगी...

विनोद की पत्नी बोली

झूठ मत बोलो बेटा...सही रेट लगाओ...

देखो ये तुम्हारा छोटा भाई है न ? इसी के लिए थोड़ा सस्ता कर दो...÷

उसने खिड़की से झाँक रहे अपने चार वर्षीय बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा...

सुंदर से बच्चे को देख कर लड़की एक तरबूज हाथों मे उठाते हुए गाड़ी के करीब आ गई..फिर लड़के के गालों पर हाथ फेर कर बोली

सचमुच मेरा भाई तो बहुत सुंदर है आँटी...

विनोद की पत्नी बच्चे से बोली दीदी को नमस्ते बोलो बेटा...

बच्चा प्यार से बोला नमस्ते दीदी...

लड़की ने गाड़ी की खिड़की खोल कर बच्चे को बाहर निकाल लिया फिर बोली

तुम्हारा नाम क्या भैया?

लड़का बोला मेरा नाम गोलू है दीदी...

बेटे को बाहर निकालने के कारण विनोद की पत्नी कुछ असहज हो गई.. तुरंत बोली अरे बेटा इसे वापस अंदर भेजो... इसे डस्ट से एलर्जी है...

लड़की उसकी आवाज पर ध्यान न देते हुए लड़के से बोली

तु तो सचमुच गोल मटोल है रे भाई...**तरबूज खाएगा?**

लड़के ने हाँ मे गर्दन हिलाई तो लड़की ने तरबूज उसके हाथों मे थमा दिया...

पाँच किलो का तरबूज गोलू नही संभाल पाया...तरबूज फिसल कर उसके हाथ से नीचे गिर गया और फूट कर तीन चार टुकड़ों मे बंट गया...तरबूज के गिर कर फुट जाने से लड़का रोने लगा...

लड़की उसे पुचकारते हुए बोली...

अरे भाई रो मत...मै दूसरा लाती हूँ...

फिर वह दौड़कर गई और एक और बड़ा सा तरबूज उठा लाई...

जब तक वह तरबूज उठा कर लाई इतनी देर मे विनोद की पत्नी ने बच्चे को अंदर गाड़ी मे खींच कर खिड़की बन्द कर ली...

लड़की खुले हुए शीशे से तरबूज अंदर देते हुए बोली -ले भाई ये बहुत मिठा निकलेगा।

विनोद चुपचाप बैठा लड़की की हरकतें देख रहा था...

विनोद की पत्नी बोली

जो तरबूज फूटा है मै उसके पैसे नही दूँगी...वह तुम्हारी गलती से फूटा है...

लड़की मुस्कराते हुए बोली उसको छोड़ो आंटी...आप इस तरबूज के पैसे भी मत देना... ये मैने अपने भाई के लिए दिया है...

इतना सुनते ही विनोद और उसकी पत्नी दोनों एक साथ चौंक पड़े...

विनोद बोला –नही बिटिया तुम अपने दोनों तरबूज के पैसे लो...÷

फिर सौ का नोट उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया...लड़की हाथ के इशारे से मना करते हुए वहाँ से हट गई...और अपने बाकी बचे तरबुजों के पास जाकर खड़ी हो गई...

विनोद भी गाड़ी से निकल कर वहाँ आ गया था...आते ही बोला...

पैसे ले लो बेटा वरना तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा...

लड़की बोली माँ कहती है जब बात रिश्तों की हो तो नफा नुकसान नही देखा जाता...आपने गोलू को मेरा भाई बताया मुझे बहुत अच्छा लगा... मेरा भी एक छोटा सा भाई था मगर..

विनोद बोला क्या हुआ तुम्हारे भाई को?

वह बोली...

जब वह दो साल का था तब उसे रात में बुखार हुआ था...सुबह माँ हॉस्पिटल मे ले जा पाती उससे पहले ही उसने दम तौड़ दिया था...मुझे मेरे भाई की बहुत याद आती है...

उससे एक साल पहले पापा भी ऐसे ही हमे छोड़ कर गुजर गए थे...

विनोद की पत्नी बोली...

ले बिटिया अपने पैसे ले ले...

लड़की बोली पैसे नही लुंगी आंटी...

विनोद की पत्नी गाड़ी मे गई फिर अपने बैग से एक पाजेब की जोड़ी निकाली...जो उसने अपनी आठ वर्षीय बेटी के लिए आज ही तीन हजार मे खरीदी थी... लड़की को देते हुए बोली...

तुमने गोलू को भाई माना तो मै तुम्हारी माँ जैसी हुई ना...अब तू ये लेने से मना नही कर सकती...

लड़की ने हाथ नही बढ़ाया तो उसने जबरदस्ती लड़की की गोद मे पाजेब रखते हुए कहा

रख ले...जब भी पहनेगी तुझे हम सब की याद आयेगी...

इतना कहकर वह वापस गाड़ी मे जाकर बैठ गई...

फिर विनोद ने गाड़ी स्टार्ट की और लड़की को बाय बोलते हुए वे चले पड़े...

विनोद गाड़ी चलाते हुए सोच रहा था कि भावुकता भी क्या चीज है...कुछ देर पहले उसकी पत्नी दस बीस रुपये बचाने के लिए हथकण्डे अपना रही थी...कुछ देर मे ही इतनी बदल गई जो तीन हजार की पाजेब दे आई... फिर अचानक विनोद को लड़की की एक बात याद आई

रिश्तों मे नफा नुकसान नहीं देखा जाता

विनोद का प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर अपने ही बड़े भाई से कोर्ट मे मुकदमा चल रहा था...

उसने तुरंत अपने बड़े भाई को फोन मिलाया...फोन उठाते ही बोला भैया मै विनोद बोल रहा हूँ...

भाई बोला फोन क्यों किया?

विनोद बोला

भैया आप वो मैन मार्केट वाली दुकान ले लो...मेरे लिए मंडी वाली छोड़ दो...

और वो बड़े वाला प्लॉट भी आप ले लो...मैं छोटे वाला ले लूंगा...

मैं कल ही मुकदमा वापस ले रहा हूँ...

सामने से काफी देर तक आवाज नही आई...

फिर उसके बड़े भाई ने कहा ÷इससे तो तुम्हे बहुत नुकसान हो जाएगा छोटे...

विनोद बोला...

भैया आज मुझे समझ मे आ गया है रिश्तों मे नफ़ा-नुकसान नही देखा जाता.. एक दूसरे की खुशी देखी जाती है...उधर से फिर खानोशी छा गई...

फिर विनोद को बड़े भाई की रोने की आवाज सुनाई दी...

विनोद बोला

÷रो रहे हो क्या भैया?

बड़ा भाई बोला इतने प्यार से पहले बात करता तो सब कुछ मै तुझे दे देता रे...अब घर आ जा... दोनों प्रेम से बैठ कर बंटवारा करेंगे...

इतनी बड़ी कड़वाहट कुछ मीठे बोल बोलते ही न जाने कहाँ चली गई थी...कल जो एक एक इंच जमीन के लिए लड़ रहे थे वे आज भाई को सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए थे...

कहानी का मोरल-

त्याग की भावना रखिये...अगर हमेशा देने को तत्पर रहोगे तो लेने वाले का भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा...

याद रखे रिश्तों मे नफा-नुकसान नही देखा जाता...

अपनो को करीब रखने के लिए कभी कभी अपना हक भी छोड़ना पड़ता है..

ड्रोन परियोजना से महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

केंद्र सरकार की नमो ड्रोन परियोजना से छत्तीसगढ़ की बिहान परियोजना से जुड़ी महिलाओं को रोजगार के नए-नए अवसर सुलभ हो रहे है। जिसके चलते आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर हो रही हैं। नमो ड्रोन योजना के तहत ग्राम पोंडी की सुश्री सीमा वर्मा और चोरभट्ठी कला की प्रितमा वस्त्रकार सफलता पूर्वक ड्रोन चलाकर खेतों में नैनों यूरिया का छिडकाव कर रहीं है। इससे किसानों के समय और कृषि लागत की बचत हो रही है। इन महिलाओं से अन्य महिलाएं भी प्रेरित हो रही है। केंद्र सरकार की महिला सशक्तिकरण की इस योजना के तहत सुश्री सीमा वर्मा और श्रीमती प्रितमा वस्त्रकार को योजना के तहत ड्रोन दिया गया है। ड्रोन देने से पहले ग्वालियर में इन महिलाओं को 15 दिन का प्रशिक्षण दिया गया। महिलाओं ने बताया कि ड्रोन के जरिए प्रति एकड़ में नैनो यूरिया के छिड़काव में 5 से 7 मिनट का समय लगता है जिससे किसानों के समय और कृषि लागत की बचत हो रही है। महिलाएं ड्रोन चलाकर आर्थिक रूप से सक्षम बन रही है। सुश्री सीमा वर्मा द्वारा अभी तक 85 एकड़ मे ड्रोन के माध्यम से छिड़काव कर 25500 की आय अर्जित की गई है। सीमा ने बताया कि ड्रोन से छिड़काव करने से किसानों को भी कृषि लागत में कमी आती है एक एकड़ में ड्रोन से छिड़काव का 300 रूपए लिया जाता है। ड्रोन परियोजना किसानों के भी लिए बेहद उपयोगी है। बिलासपुर जिले के ग्राम बेलतरा की महिलाओं को राज्य शासन द्वारा ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ड्रोन दीदियों ने एक संगठन भी बनाया है। इस संगठन में 500 महिलाएं शामिल है। बेलतरा में 8 अगस्त गुरूवार को महिला-किसान उत्पादक संगठन की वार्षिक आमसभा रखी गई थी। जहां महिलाओं को ड्रोन चलने का प्रशिक्षण भी दिया गया।

IIT से आई बड़ी खुशखबरी! खुदकुशी रोकने के लिए दे डाली छात्रों को भारी राहत....

स्टूडेंट्स सुसाइड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आईआईटी दिल्ली ने छात्रों को बड़ी राहत दे दी है। अब उन्हें आईआईटी में पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा भी IIT दिल्ली छात्रों को आत्महत्या से रोकने के लिए बेहद जरूरी कदम उठा रहा है।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) दिल्ली ने अपने स्टूडेंट्स पर रिजल्ट के दबाव को कम करते हुए न्यूनतम एवरेज स्कोर की जरूरत को खत्म कर दिया है। आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर प्रो रंजन बनर्जी ने बताया, अब तक स्टूडेंट्स को डिग्री हासिल करने के लिए एवरेज 5 CGPA (ग्रेडिंग) लाने जरूरी थे। अब स्टूडेंट्स को सेमेस्टर वाइज तय न्यूनतम क्रेडिट स्कोर करने होंगे और हर कोर्स में पासिंग ग्रेड हासिल करना होगा। स्टूडेंट्स को कोर्स में आगे बढ़ने की शर्त पर भी छूट दी गई है ताकि वो अपने कोर्स में सेमेस्टर दर सेमेस्टर आग बढ़ते रहें।

खुदकुशी से निपटने के लिए क्या कर रहा है ढ्ढञ्ज?

IIT Delhi की सेनेट ने यह फैसला पिछले कुछ सालों में हुए स्टूडेंट्स की खुदकुशी के मामलों को देखते हुए लिया है। IIT दिल्ली के डीन स्टूडेंट्स अफेयर्स प्रो आदित्य मित्तल कहते हैं, हमने पता लगाया कि कोविड महामारी के बाद कई स्टूडेंट्स व्यक्तिगत समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। ऐसे में पढ़ाई के लेवल पर दिक्कतों को डील नहीं कर पाते हैं, तो दिक्कत और बढ़ती हैं। इससे निपटने के लिए-

- हमने हर अकैडमिक ब्लॉक, मेस, हॉस्टल, क्लासेज में सभी हेल्पलाइन, काउंसलिंग की जानकारी के साथ पोस्टर लगाए हैं।
- बडी नेटवर्क पर जोर दे रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स एक-दूसरे को सपोर्ट करें। अगर कोई मामला रिपोर्ट होता है, तो मिनटों में उसे प्रशासन से मदद मिले, इस पर काम किया है और स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है।
- हमने मुश्किल मामलों में पैरंट्स की काउंसलिंग की जरूरत को जरूरी कदम में शामिल किया है।
- पढ़ाई को लेकर अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत हैं, तो अकैडमिक लेवल पर मदद दी जाएगी। उनका अलग से स्टडी प्लान और ट्यूटोरियल बनाया जाएगा। हर सेमेस्टर टीचर्स उनसे उनकी प्रोग्रेस पर बात करेंगे। साथ ही स्टूडेंट मेंटॉर तय किया जाएगा।

IIT Delhi का नया करिकुलम 2025 में

- आईआईटी दिल्ली अपने करिकुलम की समीक्षा कर रहा है। डायरेक्टर प्रो रंगन बनर्जी का कहना है कि 2025 में नया करिकुलम लागू होगा। उन्होंने कहा, डिपार्टमेंट स्तर पर काम चल रहा है। हम इंडस्ट्री और बाकी स्टेकहोल्डर्स से भी इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। करिकुलम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सवाल पर उन्होंने कहा, हमने एक कमिटी बनाई है जो रिपोर्ट देगी कि कैसे स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ एआई का इस्तेमाल करें।

IIT Delhi Placement: प्लेसमेंट कम, इंटर्नशिप ज्यादा

इंस्टीट्यूट में 2023-24 सेशन में प्लेसमेंट में 5प्रतिशत की कमी आयी है। बीटेक में इस बार 1215 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिली, जबकि 1940 ने रजिस्टर किया था। इससे पिछले साल 1287 स्टूडेंट्स को नौकरी मिली। पीएचडी स्टूडेंट्स की संख्या तो बढ़ी है मगर प्लेसमेंट सिर्फ 1त्न है। इंटर्नशिप में 5प्रतिशत इजाफा हुआ है। अधिकारियों ने कहा कि इसे बढ़ाने के लिए हम अलग अप्रोच के साथ काम कर रहे है।

अडानी के बाद सेबी निशाने पर क्यों ?

ऐसी कंपनी पर कोई कैसे भरोसा कर सकता है,जिसका काम संदेहास्पद रिपोर्ट जारी कर किसी नामी कंपनी की साख, किसी संस्था के चेयरपरसन की विश्वसनीयता पर शक पैदा करना हो। हमारे देश में कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण वही करते हैं जो शार्ट सेलिंग कंपनी अपने आका के इशारे पर भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए करती है। हिंडनबर्ग कंपनी के मकसद को हमारे देश के राजनीतिक दलों के नेता समझते नहीं है या जानबूझकर समझना नहीं चाहते हैं। वह सोचते हैं कि यह कंपनी तो उनके टारगेट को टारगेट कर रही है, इससे तो उनके आरोपों को ही बल मिलता है।

हकीकत में हिडनबर्ग कंपनी अमरीका जैसे देश का ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल वह भारत में राजनीतिक व आर्थिक अराजकता फैलाने के लिए करता है। पहले उसने अडानी को नुकसान पहुंचाने के लिए संदेहास्पद रिपोर्ट जारी की थी और भारत व अडानी के कंपनी के हमले के लिए तैयार नहीं होने के कारण वह अडानी व भारत के लोगों को नुकसान पहुंचा कर खुद करोड़ो रुपए का मुनाफा कमाया था।हिंडनबर्ग कंपनी ने इस बार अडानी को नहीं सेवी के चेयरपरसन को अपना टारगेट बनाया है तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि उसने ऐसा क्यों किया है।हकीकत यह है कि उसके पास अडानी के खिलाफ कुछ भी नया नहीं है, वही पुरानी बातें हैं,जिसे सेवी ने नकार दिया और अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी थी और कंपनी को कारण बताओं नोटिस जारी किया और पक्षपातपूर्ण शार्ट सेलिंग के मकसद से जारी रिपोर्ट को लेकर जवाब मांगा था।

हिंडनबर्ग कंपनी सच्ची होती तो वह सेवी के कारण बताओं नोटिस का जवाब देती,उसने ऐसा नहीं किया और सेवी के चेयरपर्सन पर एक रिपोर्ट जारी कर उनकी विश्वसीनीयता पर सवालिया निशान लगाने का प्रयास किया।इससे हुआ यह है कि हिंडनबर्ग कंपनी की विश्वसनीयता पर ही सवालिया निशान लग गया है।यही वजह है कि जवाब में अडानी ग्रुप के खिलाफ कोई नया सबूत पेश करने की जगह सेवी को ही सवालों के कठघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का इस बार भारत मे कोई खास असर नही हुआ। सुबह शेयर बाजार में गिरावट के बाद बाजार कुछ देर में ही संभल गया। क्योंकि हिंडनबर्ग ने इस बार जिस पर आरोप लगाया है, उसने तो साफ कह दिया है कि हिंडनबर्ग जो आज बता रहा है, वह तो पहले ही सरकार को बता चुकी हैं। यानी हिंडनबर्ग पुरानी बात को उजाकर भारत मे बवाल पैदा करने को सोच रहा था, वैसा कुछ नहीं हुआ तो इसलिए कि बवाल होने का चांस ही नही था।

रिपोर्ट में भी बवाल होने लायक कुछ नही था।सेवी की चेयरपर्सन व अडानी ग्रुप की तरफ से भी सही समय पर रिपोर्ट पर बयान जारी कर दिया गया, इसका असर यह हुआ कि पिछली बार की तरह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से शेयर बाजार को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। विपक्ष जरूर हमेशा की तरह उत्साहित हो गया कि उसे अड़ानी के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा मिल गया है।कांग्रेस ने तो हमेशा की तरह इसे अडानी का महाघोटाला बताकर जेपीसी से जांच कराने की मांग कर दी। कांग्रेस भी जानती है कि अगर हिंडनबर्ग के पास अडानी के खिलाफ कोई दस्तावेजी सबूत होता

तो वह यह रिपोर्ट माधवी बुच के खिलाफ नहीं अडानी के खिलाफ जारी करता। हिंडनबर्क ने अडानी की जगह माधवी बुच पर हमला किया है तो साफ है कि वह बचाव की मुद्रा में है, अपनी साख बचाने के लिए वह सेवी चेयरपरसन की साख पर शक पैदा करना चाहता है।

यह शक पैदा होता यदि सेवी चेयरपरसन ने कुछ छिपाया होता। कुछ गलत किया होता। उन्होंने इंकार किया होता कि हिंडनबर्ग ने जो बताया वह गलत है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट इस बार धमाका करने की बजाय फुस्स हो गई है।राहुल गांधी व कांग्रेस को फिर निराशा होगी कि वह मोदी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक ठोस मामला तक नहीं तलाश कर पा रहे हैं। ऐसे में तो जनता यही मानेगी कि इस मामले में वह विदेशी ताकतों का मोहरा बन कर रह गए हैं।इससे राहुल गांधी व कांग्रेस की साख कम होती है। राफेल, हिडनबर्ग,पेगासस हर मामले में कांग्रेस नेता झूठे साबित हुए हैं क्योंकि वह बिना सोच समझे ही विदेशी कंपनी की रिपोर्ट व खबर पर यकीन कर लेते हैं। वह सोचते तक नहीं है कि इस विदेशी कंपनी का मकसद कहीं देश को नुकसान पहुंचाना तो नहीं है।

श्रावण मास और रक्षाबंधन पर्व...

रक्षाबन्धन भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबन्धन का त्योहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार भाई-बहन को स्नेह की डोर में बांधता है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बन्धन बांधती है, जिसे राखी कहते हैं। यह एक हिन्दू व जैन त्योहार है जो प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण (सावन) में मनाये जाने के कारण इसे श्रावणी (सावनी) या सलूनो भी कहते हैं।[3] रक्षाबन्धन में राखी या रक्षासूत्र का सबसे अधिक महत्त्व है। राखी कच्चे सूत जैसे सस्ती वस्तु से लेकर रंगीन कलावे, रेशमी धागे, तथा सोने या चाँदी जैसी मँहगी वस्तु तक की हो सकती है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का प्रसिद्ध त्योहार है, रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य है। रक्षाबंधन के दिन बहने भगवान से अपने भाईयों की तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। राखी सामान्यतः बहनें भाई को ही बाँधती हैं परन्तु ब्राह्मणों, गुरुओं और परिवार में छोटी लड़कियों द्वारा सम्मानित सम्बंधियों (जैसे पुत्री द्वारा पिता को) भी बाँधी जाती है। कभी-कभी सार्वजनिक रूप से किसी नेता या प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी राखी बाँधी जाती है। रक्षाबंधन के दिन भाई अपने बहन को राखी के बदले कुछ उपहार देते है।

हिन्दू धर्म के सभी धार्मिक अनुष्ठानों में रक्षासूत्र बाँधते समय कर्मकाण्डी पण्डित या आचार्य संस्कृत में एक श्लोक का उच्चारण करते हैं, जिसमें रक्षाबन्धन का सम्बन्ध राजा बलि से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है (यह श्लोक रक्षाबन्धन का अभीष्ट मन्त्र -)-

येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल।
तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे मा चल मा चल ॥

इस श्लोक का हिन्दी भावार्थ है- जिस रक्षासूत्र से महान शक्तिशाली दानवेन्द्र राजा बलि को बाँधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुझे बाँधती हूँ। हे रक्षे (राखी)! तुम अडिग रहना (तू अपने संकल्प से कभी भी विचलित न हो।)÷

प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर लड़कियाँ और महिलाएँ पूजा की थाली सजाती हैं। थाली में राखी के साथ रोली या हल्दी, चावल, दीपक, मिठाई और कुछ पैसे भी होते हैं। लड़के और पुरुष तैयार होकर टीका करवाने के लिये पूजा या किसी उपयुक्त स्थान पर बैठते हैं। पहले अभीष्ट देवता की पूजा की जाती है, इसके बाद रोली या हल्दी से भाई का टीका करके चावल को टीके पर लगाया जाता है और सिर पर छिड़का जाता है, उसकी आरती उतारी जाती है, दाहिनी कलाई पर राखी बाँधी जाती है और पैसों से न्यौछावर करके उन्हें गरीबों में बाँट दिया जाता है। भारत के अनेक प्रान्तों में भाई के कान के ऊपर भोजली या भुजरियाँ लगाने की प्रथा भी है। भाई बहन को उपहार या धन देता है। इस प्रकार रक्षाबन्धन के अनुष्ठान को पूरा करने के बाद ही भोजन किया जाता है। प्रत्येक पर्व की तरह उपहारों और खाने-पीने के विशेष पकवानों का महत्त्व रक्षाबन्धन में भी होता है। आमतौर पर दोपहर का भोजन महत्त्वपूर्ण होता है और रक्षाबन्धन

का अनुष्ठान पूरा होने तक बहनों द्वारा व्रत रखने की भी परम्परा है। पुरोहित तथा आचार्य सुबह-सुबह यजमानों के घर पहुँचकर उन्हें राखी बाँधते हैं और बदले में धन, वस्त्र और भोजन आदि प्राप्त करते हैं। यह पर्व भारतीय समाज में इतनी व्यापकता और गहराई से समाया हुआ है कि इसका सामाजिक महत्त्व तो है ही, धर्म, पुराण, इतिहास, साहित्य और फ़िल्में भी इससे अछूते नहीं हैं।

इस दिन बहनें अपने भाई के दायें हाथ पर राखी बाँधकर उसके माथे पर तिलक करती हैं और उसकी दीर्घ आयु की कामना करती हैं। बदले में भाई उनकी रक्षा का वचन देता है। ऐसा माना जाता है कि राखी के रंगबिरंगे धागे भाई-बहन के प्यार के बन्धन को मज़बूत करते है। भाई बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और सुख-दुख में साथ रहने का विश्वास दिलाते हैं। यह एक ऐसा पावन पर्व है जो भाई-बहन के पवित्र रिश्ते को पूरा आदर और सम्मान देता है।

सगे भाई बहन के अतिरिक्त अनेक भावनात्मक रिश्ते भी इस पर्व से बँधे होते हैं जो धर्म, जाति और देश की सीमाओं से परे हैं। रक्षाबन्धन का पर्व भारत के राष्ट्पति और प्रधानमन्त्री के निवास पर भी मनाया जाता है। जहाँ छोटे छोटे बच्चे जाकर उन्हें राखी बाँधते हैं। रक्षाबन्धन आत्मीयता और स्नेह के बन्धन से रिश्तों को मज़बूती प्रदान करने का पर्व है। यही कारण है कि इस अवसर पर न केवल बहन भाई को ही अपितु अन्य सम्बन्धों में भी रक्षा (या राखी) बाँधने का प्रचलन है। गुरु शिष्य को रक्षासूत्र बाँधता है तो शिष्य गुरु को। भारत में प्राचीन काल में जब स्नातक अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात गुरुकुल से विदा लेता था तो वह आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उसे रक्षासूत्र बाँधता था जबकि आचार्य अपने विद्यार्थी को इस कामना के साथ रक्षासूत्र बाँधता था कि उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह अपने भावी जीवन में उसका समुचित ढंग से प्रयोग करे ताकि वह अपने ज्ञान के साथ-साथ आचार्य की गरिमा की रक्षा करने में भी सफल हो। इसी परम्परा के अनुरूप आज भी किसी धार्मिक विधि विधान से पूर्व पुरोहित यजमान को रक्षासूत्र बाँधता है और यजमान पुरोहित को। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के सम्मान की रक्षा करने के लिये परस्पर एक दूसरे को अपने बन्धन में बाँधते हैं।

रक्षाबन्धन पर्व सामाजिक और पारिवारिक एकबद्धता या एकसूत्रता का सांस्कृतिक उपाय रहा है। विवाह के बाद बहन पराये घर में चली जाती है। इस बहाने प्रतिवर्ष अपने सगे ही नहीं अपितु दूरदराज के रिश्तों के भाइयों तक को उनके घर जाकर राखी बाँधती है और इस प्रकार अपने रिश्तों का नवीनीकरण करती रहती है। दो परिवारों का और कुलों का पारस्परिक योग (मिलन) होता है। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच भी एकसूत्रता के रूप में इस पर्व का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार जो कड़ी टूट गयी है उसे फिर से जागृत किया जा सकता है।

रक्षाबन्धन के अवसर पर कुछ विशेष पकवान भी बनाये जाते हैं जैसे घेवर, शकरपारे, नमकपारे और घुघनी। घेवर सावन का विशेष मिष्ठान्न है यह केवल हलवाई ही बनाते हैं जबकि शकरपारे और नमकपारे आमतौर पर घर में ही बनाये जाते हैं। घुघनी बनाने के लिये काले चने को उबालकर चटपटा छौंका जाता है। इसको पूरी और दही के साथ खाते हैं। हलवा और खीर भी इस पर्व के लोकप्रिय पकवान हैं।

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में रक्षा बन्धन पर्व की भूमिका

हमें सबसे प्राचीन दो कथाएं मिलती है। पहली भविष्य पुराण में इंद्र और शची की कथा और दूसरी श्रीमद्भागवत पुराण में वामन और बाली की कथा। अब दोनों ही कथा का समय काल निर्धारित करना कठिन है। राजा बली भी इंद्र के ही काल में हुए थे। उन्होंने भी देवासुर संग्राम में भाग लिया था। यह ढूंढना थोड़ा मुश्किल है कि कौनसी घटना पहले घटी। फिर भी जानकार कहते हैं कि पहले समुद्र मंथन हुआ फिर वामन अवतार।

1.भविष्य पुराण में कहीं पर लिखा है कि देव और असुरों में जब युद्ध शुरू हुआ, तब असुर या दैत्य देवों पर भारी पड़ने लगे। ऐसे में देवताओं को हारता देख देवेंद्र इन्द्र घबराकर ऋषि बृहस्पति के पास गए। तब बृहस्पति के सुझाव पर इन्द्र की पत्नी इंद्राणी (शची) ने रेशम का एक धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ पर बांध दिया। संयोग से वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। जिसके फलस्वरूप इंद्र विजयी हुए। कहते हैं कि तब से ही पत्नियां अपने पति की कलाई पर युद्ध में उनकी जीत के लिए राखी बांधने लगी।

2. दूसरी कथा हमें स्कंद पुराण, पद्मपुराण और श्रीमद्भागवत पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार असुरराज दानवीर राजा बली ने देवताओं से युद्ध करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था और ऐसे में उसका अहंकार चरम पर था। इसी अहंकार को चूर-चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में राजा बली के द्वार भिक्षा मांगने पहुंच गए।

चूंकि राज बली महान दानवीर थे तो उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो भी मांगोगे मैं वह दूंगा। भगवान ने बलि से भिक्षा में तीन पग भूमि की मांग ली। बली ने तत्काल हां कर दी, क्योंकि तीन पग ही भूमि तो देना थी। लेकिन तब भगवान वामन ने अपना विशालरूप प्रकट किया और दो पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप लिया। फिर पूछा कि राजन अब बताइये कि तीसरा पग कहां रखूं? तब विष्णुभक्त राजा बली ने कहा, भगवान आप मेरे सिर पर रख लीजिए और फिर भगवान ने राजा बली को रसातल का राजा बनाकर अजर-अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बली ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान से रात-दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया।

भगवान को वामनावतार के बाद पुन- लक्ष्मी के पास जाना था लेकिन भगवान ये वचन देकर फंस गए और वे वहीं रसातल में बली की सेवा में रहने लगे। उधर, इस बात से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। ऐसे में नारदजी ने लक्ष्मीजी को एक उपाय बताया। तब लक्ष्मीजी ने राजा बली को राखी बांध अपना भाई बनाया और अपने पति को अपने साथ ले आई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से यह रक्षा बंधन का त्योहार प्रचलन में हैं।

पौराणिक प्रसंग

राखी का त्योहार कब शुरू हुआ यह कोई नहीं जानता। लेकिन भविष्य पुराण में वर्णन मिलता है कि देव और दानवों में जब युद्ध शुरू हुआ तब दानव हावी होते नज़र आने लगे। भगवान इन्द्र घबरा कर बृहस्पति के पास गये। वहां बैठी इन्द्र की पत्नी इंद्राणी सब सुन रही थी। उन्होंने रेशम का धागा मन्त्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ पर बाँध दिया। संयोग से वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। लोगों का विश्वास है कि इन्द्र इस लड़ाई में इसी धागे की मन्त्र शक्ति से ही विजयी हुए थे। उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन यह धागा बाँधने की प्रथा चली आ रही है। यह धागा धन, शक्ति, हर्ष और विजय देने में पूरी तरह समर्थ माना जाता है।

इतिहास मे कृष्ण और द्रौपदी की कहानी प्रसिद्व है, जिसमे युद्ध के दौरान श्री कृष्ण की उंगली घायल हो गई थी, श्री कृष्ण की घायल उंगली को द्रौपदी ने अपनी साड़ी मे से एक टुकड़ा बाँध दिया था, और इस उपकार के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को किसी भी संकट मे द्रौपदी की सहायता करने का वचन दिया था। स्कन्ध पुराण, पद्मपुराण और श्रीमद्भागवत में वामनावतार नामक कथा में रक्षाबन्धन का प्रसंग मिलता है।

कथा कुछ इस प्रकार है, दानवेन्द्र राजा बलि ने जब 100 यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग का राज्य छीनने का प्रयत्न किया तो इन्द्र आदि देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान वामन अवतार लेकर ब्राह्मण का वेष धारण कर राजा बलि से भिक्षा माँगने पहुँचे। गुरु के मना करने पर भी बलि ने तीन पग भूमि दान कर दी। भगवान ने तीन पग में सारा आकाश पाताल और धरती नापकर राजा बलि को रसातल में भेज दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु द्वारा बलि राजा के अभिमान को चकनाचूर कर देने के कारण यह त्योहार बलेव नाम से भी प्रसिद्ध है। कहते हैं एक बार बलि रसातल में चला गया तब बलि ने अपनी भक्ति के बल से भगवान को रात-दिन अपने सामने रहने का वचन ले लिया।[ङ] भगवान के घर न लौटने से परेशान लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय बताया। उस उपाय का पालन करते हुए लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे रक्षाबन्धन बांधकर अपना भाई बनाया और अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ ले आयीं। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। विष्णु पुराण के एक प्रसंग में कहा गया है कि श्रावण की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने हयग्रीव के रूप में अवतार लेकर वेदों को ब्रह्मा के लिये फिर से प्राप्त किया था। भगवान हयग्रीव को विद्या और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है।

ऐतिहासिक प्रसंग

राजपूत जब लड़ाई पर जाते थे तब महिलाएँ उनको माथे पर कुमकुम तिलक लगाने के साथ साथ हाथ में रेशमी धागा भी बाँधती थी। इस विश्वास के साथ कि यह धागा उन्हे विजयश्री के साथ वापस ले आयेगा। राखी के साथ एक और प्रसिद्ध कहानी जुड़ी हुई है। कहते हैं, मेवाड़ की रानी कर्मावती को बहादुरशाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की पूर्व सूचना मिली। रानी लड़ने में असमर्थ थी अत- उसने मुगल बादशाह हुमायूँ को राखी भेज कर रक्षा की याचना की। हुमायूँ ने मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुँच कर बहादुरशाह के विरूद्ध मेवाड़ की ओर से लड़ते हुए कर्मावती व उसके राज्य की रक्षा की। एक अन्य प्रसंगानुसार सिकन्दर की पत्नी ने अपने पति के हिन्दू शत्रु पुरूवास को राखी बाँधकर अपना मुँहबोला भाई बनाया और युद्ध के समय सिकन्दर को न मारने का वचन लिया। पुरूवास ने युद्ध के दौरान हाथ में बँधी राखी और अपनी बहन को दिये हुए वचन का सम्मान करते हुए सिकन्दर को जीवन-दान दिया।

महाभारत में भी इस बात का उल्लेख है कि जब ज्येष्ठ पाण्डव युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ तब भगवान कृष्ण ने उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिये राखी का त्योहार मनाने की सलाह दी थी। उनका कहना था कि राखी के इस रेशमी धागे में वह शक्ति है जिससे आप हर आपत्ति से मुक्ति पा सकते हैं। इस समय द्रौपदी द्वारा कृष्ण को तथा कुन्ती द्वारा अभिमन्यु को राखी बाँधने के कई उल्लेख मिलते हैं। महाभारत में ही रक्षाबन्धन से सम्बन्धित कृष्ण और द्रौपदी का एक और वृत्तान्त भी मिलता है। जब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तब उनकी तर्जनी में चोट आ गई। द्रौपदी ने उस समय अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उँगली पर पट्टी बाँध दी। यह

श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। कृष्ण ने इस उपकार का बदला बाद में चीरहरण के समय उनकी साड़ी को बढ़ाकर चुकाया। कहते हैं परस्पर एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना रक्षाबन्धन के पर्व में यहीं से प्रारम्भ हुई।

साहित्यिक प्रसंग

अनेक साहित्यिक ग्रन्थ ऐसे हैं जिनमें रक्षाबन्धन के पर्व का विस्तृत वर्णन मिलता है। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है हरिकृष्ण प्रेमी का ऐतिहासिक नाटक रक्षाबन्धन जिसका 1991 में 18वाँ संस्करण प्रकाशित हो चुका है। मराठी में शिन्दे साम्राज्य के विषय में लिखते हुए रामराव सुभानराव बर्गे ने भी एक नाटक की रचना की जिसका शीर्षक है राखी ऊर्फ रक्षाबन्धन। पचास और साठ के दशक में रक्षाबन्धन हिंदी फ़िल्मों का लोकप्रिय विषय बना रहा। ना सिर्फ़ राखी नाम से बल्कि रक्षाबन्धन नाम से भी कई फ़िल्में बनायीं गयीं। राखी नाम से दो बार फ़िल्मा बनी, एक बार सन 1949 में, दूसरी बार सन 1962 में, सन 62 में आई फ़िल्म को ए. भीमसिंह ने बनाया था, कलाकार थे अशोक कुमार, वहीदा रहमान, प्रदीप कुमार और अमिता। इस फ़िल्मं में राजेंद्र कृष्णय ने शीर्षक गीत लिखा था- ÷राखी धागों का त्यौहार। सन 1972 में एस.एम.सागर ने फ़िल्म बनायी थी राखी और हथकड़ी इसमें आर.डी.बर्मन का संगीत था। सन 1976 में राधाकान्त शर्मा ने फ़िल्मा बनाई राखी और राइफल। दारा सिंह के अभिनय वाली यह एक मसाला फ़िल्मन थी। इसी तरह से सन 1976 में ही शान्तिलाल सोनी ने सचिन और सारिका को लेकर एक फ़िल्मा रक्षाबन्धन नाम की भी बनायी थी।

सरकारी प्रबन्ध

भारत सरकार के डाक-तार विभाग द्वारा इस अवसर पर दस रुपए वाले आकर्षक लिफाफों की बिक्री की जाती हैं। लिफाफे की कीमत 5 रुपए और 5 रुपए डाक का शुल्क। इसमें राखी के त्योहार पर बहनें, भाई को मात्र पाँच रुपये में एक साथ तीन-चार राखियाँ तक भेज सकती हैं। डाक विभाग की ओर से बहनों को दिये इस तोहफे के तहत 50 ग्राम वजन तक राखी का लिफाफा मात्र पाँच रुपये में भेजा जा सकता है जबकि सामान्य 20 ग्राम के लिफाफे में एक ही राखी भेजी जा सकती है। यह सुविधा रक्षाबन्धन तक ही उपलब्ध रहती है। रक्षाबन्धन के अवसर पर बरसात के मौसम का ध्यान रखते हुए डाक-तार विभाग ने 2007 से बारिश से ख़राब न होने वाले वाटरप्रूफ लिफाफे भी उपलब्ध कराये हैं। ये लिफाफे अन्य लिफाफों से भिन्न हैं। इसका आकार और डिजाइन भी अलग है जिसके कारण राखी इसमें ज्यादा सुरक्षित रहती है। डाक-तार विभाग पर रक्षाबन्धन के अवसर पर 20 प्रतिशत अधिक काम का बोझ पड़ता है। अतः राखी को सुरक्षित और तेजी से पहुँचाने के लिए विशेष उपाय किये जाते हैं और काम के हिसाब से इसमें सेवानिवृत्त डाककर्मियों की सेवाएँ भी ली जाती है। कुछ बड़े शहरों के बड़े डाकघरों में राखी के लिये अलग से बाक्स भी लगाये जाते हैं। इसके साथ ही चुनिन्दा डाकघरों में सम्पर्क करने वाले लोगों को राखी बेचने की भी इजाजत दी जाती है, ताकि लोग वहीं से राखी खरीद कर निर्धारित स्थान को भेज सकें।

राखी और आधुनिक तकनीकी माध्यम

आज के आधुनिक तकनीकी युग एवं सूचना सम्प्रेषण युग का प्रभाव राखी जैसे त्योहार पर भी पड़ा है। बहुत सारे भारतीय आजकल विदेश में रहते हैं एवं उनके परिवार वाले (भाई एवं बहन) अभी भी भारत या अन्य देशों में हैं। इण्टरनेट के आने के बाद कई सारी ई-कॉमर्स साइट खुल गयी हैं जो ऑनलाइन आर्डर लेकर राखी दिये गये पते पर पहुँचाती है।[35] इसके अतिरिक्त भारत में 2007 राखी के अवसर पर इस पर्व से सम्बन्धित एक एनीमेटेड सीडी भी आ गयी है जिसमें एक बहन द्वारा भाई को टीका करने व राखी बाँधने का चलचित्र है। यह सीडी राखी के अवसर पर अनेक बहनें दूर देश में रहने वाले अपने भाइयों को भेज सकती हैं।

रक्षाबंधन के बहुत बहुत बधाई ...

सावन को शिव का महीना क्यों माना जाता है, आखिर क्यों पसंद है शिव जी को सावन ?

सावन इसे शिव का महीना माना जाता है और पूरे महीने शिव आराधना की जाती है। जिसमें रूद्राभिषेक के बाद बिल्वपत्र और भस्म चढ़ाने समेत कई परंपराए शामिल हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों शिवजी को सावन का महीना पसंद है और इस महीने का नाम सावन कैसे पड़ा...? आइए समझते हैं शिव पूजा की परंपराएं और कथाओं से...

सावन, दक्षिणायन में आता है। जिसके देवता शिव हैं, इसीलिए इन दिनों उन्हीं की आराधना शुभ फलदायक होती है। सावन के दौरान बारिश का मौसम होता है। पुराणों के मुताबिक शिवजी को चढ़ने वाले फूल-पत्ते बारिश में ही आते हैं इसलिए सावन में शिव पूजा की परंपरा बनी।

स्कंद पुराण में भगवान शिव ने सनत्कुमार को सावन महीने के बारे में बताया कि मुझे श्रावण बहुत प्रिय है। इस महीने की हर तिथि व्रत और हर दिन पर्व होता है, इसलिए इस महीने नियम-संयम से रहते हुए पूजा करने से शक्ति और पुण्य बढ़ते हैं।

शिवजी को क्यों पसंद है सावन ?

ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती जी ने सावन के महीने में ही बिना कुछ खाए पिए शिवजी के लिए कठिन व्रत रखा और शिव जी को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया। एक मान्यता यह भी है कि भगवान् शिव सावन के महीने में ही पृथ्वी पर अपने ससुराल गए थे ,जहाँ उनका जलाभिषेक कर स्वागत किया गया था। इसलिए यह भी माना जाता है कि भगवान् शिव प्रतिवर्ष सावन में ही अपने ससुराल आते हैं।

इस महीने का नाम श्रावण क्यों...?

स्कंद और शिव पुराण के हवाले से जानकार इसकी दो वजह बताते हैं। पहली, इस महीने पूर्णिमा तिथि पर श्रवण नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के कारण ही महीने का ये नाम पड़ा।

दूसरी वजह, भगवान शिव ने सनत्कुमार को बताया कि इसका महत्व सुनने के योग्य है। जिससे सिद्धि मिलती है, इसलिए इसे श्रावण कहते हैं। इसमें निर्मलता का गुण होने से ये आकाश के समान है, इसलिए इसे नभा भी कहा गया है।

सावन का महत्व बताते हुए महाभारत के अनुशासन पर्व में अंगिरा ऋषि ने कहा है कि जो इंसान मन और इन्द्रियों को काबू में रखकर एक वक्त खाना खाते हुए श्रावण मास बिताता है, उसे कई तीर्थों में स्नान करने जितना पुण्य मिलता है।

क्यों करते हैं रुद्राभिषेक ?

सावन मॉस में ही समुद्र मंथन हुवा था। जिसमे हलाहल विष निकला था। जिसे भगवान् शिव जी ने अपने गले में धारण कर सम्पूर्ण दुनिया को बचाया था। परन्तु इस जहर के ग्रहण करने से उनके शरीर में गर्मी बढ़ गयी थी। जहर के असर को कम करने के लिए समस्त देवी-देवताओं ने जल चढ़ाया। तब से शिवलिंग पर जलाभिषेक की परम्परा बनी।

क्यों चढाते हैं बिल्वपत्र ?

पुरानों के अनुसार शिवजी ने कहा कि मेरे बाएं नेत्र में चन्द्रमा ,दायें नेत्र में सूर्य और बीच में अग्नि का वास है। और बिल्वपत्र शिवजी के त्रिनेत्र का प्रतीक है। बिल्वपत्र चढाने से भगवान शिव के साथ ही साथ सूर्य,चन्द्र और अग्नि की पूजा भी हो जाती है। स्कन्दपुराण के अनुसार बेल के पेड़ में देवी गिरिजा,महेश्वरी,दाक्षायनी, पार्वती, गौरी और कात्यायनी का वास रहता है। इसलिए बिल्व पत्र चढाने से इन समस्त देवियों की भी पूजा हो जाती हैं।

पार्वती की परीक्षा

देवी सती ने ही पार्वती के रूप में दूसरा जन्म लिया था। इस जन्म में भी शिव को पति के रूप में पाने के लिए वे कठिन तप कर रही थीं। शिव ने पहले सप्तर्षियों को परीक्षा के लिए भेजा। सप्तर्षियों ने पार्वती के पास पहुंचकर शिवजी की बहुत बुराई की, उनके दोष गिनाए, लेकिन पार्वती अपने संकल्प पर अडिग रहीं। इसके बाद महादेव खुद आए। उन्होंने पार्वती जी को वरदान दिया और अंतर्धान हो गए।

तभी एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। पार्वती जहां तप कर रही थीं, उसी के पास मौजूद तालाब में मगरमच्छ ने एक बच्चे का पैर पकड़ रखा था। पार्वती वहां पहुंचीं और मगरमच्छ से बच्चे को छोड़ने को कहा। मगरमच्छ ने अपना नियम बताते हुए इनकार किया कि दिन के छठे पहर में जो मिलता है, उसे आहार बना लेता हूं। इस पर पार्वती ने पूछा, इसे छोड़ने के बदले क्या चाहोगे? मगरमच्छ ने कहा, अपने तप का फल मुझे दे देंगी, तो बालक को छोड़ दूंगा।

पार्वती तत्काल तैयार हो गईं, पर मगरमच्छ ने उन्हें समझाया कि वे क्यों एक बालक के लिए अपने कठिन तप का फल दे रही हैं, लेकिन पार्वती ने दान का संकल्प किया। उनके ऐसा करते ही मगर का शरीर चमकने लगा। अचानक बच्चा और मगर, दोनों गायब हो गए और उनकी जगह शिव प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि वो परीक्षा ले रहे थे। चूंकि पार्वती ने अपने तप का फल शिव को ही दिया था, इसलिए उन्हें दोबारा तप करने की जरूरत नहीं रही।

कामदेव को भस्म किया

शिव को कामांतक भी कहते हैं। इसके पीछे कथा है। तारकासुर ने ब्रह्माजी से दो वरदान पाए थे। पहला, तीनों लोकों में उसके समान ताकतवर कोई न हो और दूसरा, शिवपुत्र ही उसे मार सके। तारकासुर जानता था कि देवी सती के देहांत के बाद शिव समाधि में जा चुके हैं, जिससे शिवपुत्र होना असंभव था। वरदान पाकर तारकासुर ने तीनों लोकों को जीत लिया। उसके अत्याचार से परेशान होकर देवता ब्रह्माजी के पास गए।

उन्होंने देवताओं को वरदान के बारे में बताते हुए कहा कि केवल शिवपुत्र ही तारकासुर को मार सकता है, लेकिन शिवजी गहरी समाधि में हैं। हिमवान की पुत्री पार्वती शिव से विवाह के लिए तप कर रही हैं, लेकिन वे पार्वती की तरफ देखना भी नहीं चाहते, अगर महादेव पार्वती से विवाह कर पुत्र उत्पन्न करें, तभी इस दैत्य का वध संभव है।

तब इंद्र ने कामदेव से कहा कि वे जाकर शिवजी के मन में देवी पार्वती के प्रति अनुराग जगाएं। कामदेव ने पुष्पबाण ध्यानमग्न शिवजी पर चला दिया। अचानक इस विघ्न से शिवजी बेहद गुस्सा हुए और उन्होंने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया ।

इस पर कामदेव की पत्नी रति ने शिवजी से प्रार्थना की कि वे उसके पति का जीवन वापस लौटा दें। शिव ने शांत होकर कहा, कामदेव की देह नष्ट हुई है, लेकिन उसकी आंतरिक शक्ति नहीं। काम अब देह रहित होकर हर प्राणी के हृदय में रहेगा। वह कृष्णावतार के समय कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा। तुम फिर उसकी पत्नी बनोगी। उस समय रति ने मायावती के रूप में जन्म लिया था।

अशुभ से हुआ शुभ

नर्मदा नदी के किनारे धर्मपुर नाम का सुंदर नगर था। उसमें विश्वानर नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुचिस्मति के साथ रहता था। दोनों शिव भक्त थे और उन्होंने पुत्र पाने के लिए उनसे वरदान मांगा कि स्वयं भगवान शिव उनके पुत्र के रूप में जन्म लें।

शिव के वरदान से उनके यहां एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम गृहपति था। जब बालक ग्यारह साल का था, तब देवर्षि नारद ने उसका हाथ देखकर भविष्यवाणी की कि सालभर के भीतर उसके साथ कुछ अशुभ होगा, जो आग से जुड़ा होगा। जब मां-बाप ये सुनकर दुखी हुए, तो बेटे ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि वे दुखी न हों, क्योंकि वह भगवान को प्रसन्न कर लेगा। इससे अनिष्ट टल जाएगा।

माता-पिता से आज्ञा लेकर वह शिव की नगरी काशी पहुंचा। वहां उसने गंगा के मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया और पूरे साल शिवलिंग की पूजा की। जब नारद मुनि द्वारा बताया अनिष्ट समय आया, तो देवराज इंद्र ने प्रकट होकर उससे वरदान मांगने को कहा। बालक ने वरदान लेने से मना किया और कहा वो केवल भगवान शिव से ही वर प्राप्त करेगा। ये सुनकर इंद्र बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने इस बालक को सबक सिखाने के लिए वज्र उठा लिया। बालक ने भगवान शिव से रक्षा की याचना की। तभी शिव प्रकट होकर बोले- डरो मत। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए इंद्र के वेश में आया था। मैं तुम्हें अग्नीश्वर नाम देता हूं। तुम आग्नेय दिशा (दक्षिण-पूर्व दिशा) के रक्षक होगे। जो भी तुम्हारा भक्त होगा, उसको अग्नि, बिजली या अकाल मृत्यु का डर नहीं होगा। अग्नि को शिव का एक रूप कहते हैं। वो शिव का तीसरा नेत्र भी है।

आज बंगाल में विरोध राजनीतिक लड़ाई में तब्दील होने के ख़तरे में...

सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के साथ हुए भयानक बलात्कार और हत्या के एक हफ़्ते से ज़्यादा समय बाद, कोलकाता विरोध के एक छोटे से गणतंत्र में तब्दील हो गया है। जो बात नागरिकों के अचानक आक्रोश के रूप में शुरू हुई थी, जिसमें दुख और असहायता की भावना ने आग में घी डाला था, वह अब स्पष्ट रूप से एक राजनीतिक लड़ाई में तब्दील होने के ख़तरे में है, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत वैधता के लिए सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है।

विपक्षी भाजपा ने अपनी भूमिका के अनुसार, इस मामले में और तेज़ी ला दी है। यह कई स्तरों पर राज्य की संस्थागत विफलताओं के ख़िलाफ़ विरोध कर रही है, जिसका पैमाना और सीमा निर्विवाद है। सत्तारूढ़ तृणमूल सरकार, जो स्पष्ट रूप से हार चुकी है और जिसके पास विश्वसनीय प्रतिक्रिया का अभाव है, उस अपराध के लिए कठोर सज़ा की ज़रूरत पर ज़ोरदार आवाज़ में चिल्ला रही है, जिसने पूरे देश का ध्यान बंगाल की ओर खींचा है। पुलिस की हालत खस्ता है। न्यायपालिका द्वारा उनके पंख काटे जाने और उनकी खिल्ली उड़ाए जाने के बाद, पुलिस को अफवाहों और सोशल मीडिया के दुस्साहस के बारे में शिकायत करनी पड़ रही है। छात्र, जो हमेशा से उदासीन राज्य के निशाने पर रहे हैं, अपना विरोध जारी रखे हुए हैं। बहादुरी और खामोशी से आगे बढ़ रहे हैं।

इस अपराध की अंतर्निहित परिस्थितियाँ राज्य के दो विशिष्ट अंगों से संबंधित हैं- पुलिस और स्वास्थ्य, दोनों ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रत्यक्ष निगरानी में हैं। लेकिन वह भी विरोध कर रही हैं, सीबीआई द्वारा की जा रही जांच के त्वरित समाधान की मांग के लिए एक मार्च निकाल रही हैं। तो, अगर हर कोई विरोध कर रहा है, तो कौन सुन रहा है? निवारण पर काम करने के लिए कौन बचा है? शब्दार्थ को अलग रखते हुए, मुख्यमंत्री शुक्रवार को मृत डॉक्टर के लिए न्याय मांगने के लिए सड़कों पर उतरीं, जिसका प्रभावी अर्थ यह है कि राज्य के ÷स्वास्थ्य मंत्री÷ राज्य के ÷गृह मंत्री÷ से मांग कर रहे हैं कि इस जघन्य अपराध के दोषियों की पहचान की जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए और उन्हें सजा दी जाए। इस क्रूर तमाशे की त्रासदी यह है कि एक मुख्यमंत्री, जो अल्पकालिक क्षति नियंत्रण की हताश आवश्यकता से अंधी हो गई है, यह भी नहीं देख पा रही है कि उसके कार्य कितने विचित्र, हास्यास्पद लग सकते हैं। इसलिए, क्या दीदी ÷आंदोलन÷ का उपयोग नहीं कर रही हैं, जिसका उद्देश्य और पवित्रता उन्हें किसी सबक की आवश्यकता नहीं है, जिम्मेदारी से बचने के साधन के रूप में? पूरे देश में, वह एक उत्साही सड़क योद्धा के रूप में जानी जाती हैं और आम तौर पर उनकी प्रशंसा की जाती है। अपनी पार्टी के आकर्षक कहावत ÷माँ, माटी, मानुष÷ के प्रति आभारी होने के बल पर, वह एक विशालकाय, सीपीएम के नेतृत्व वाली राजनीतिक व्यवस्था को हटाने में सफल रही है, जो तीन दशकों से सत्ता में थी और राज्य विधानसभा में शून्य पर सिमट गई। फिर भी, अब मुख्यमंत्री के रूप में अपने लगातार तीसरे कार्यकाल में, दीदी उन राजनीतिक आलोचनाओं से बचने या उन्हें टालने में असमर्थ हैं, जिनका सामना उन्हें करना पड़ रहा है। दुर्भाग्य से, उन्हें केवल खुद को ही दोषी ठहराना है। संस्थागत खामियों से निपटने और उन कई खामियों को दूर करने के बजाय, जिन्हें वह और उनका प्रशासन इन सभी क्षेत्रों में वर्षों से छिपाते आ रहे हैं, वह पदयात्रा में शरण लेती हैं, जिसके दौरान वह ÷राम÷ और ÷बाम÷ का नाम लेकर खुद को दोहराती हैं, भाजपा और लगभग विलुप्त हो चुके वामपंथ के खिलाफ साजिश की कहानी गढ़ती हैं। क्या दीदी अपनी सारी बुद्धि के बावजूद यह नहीं देख पा रही हैं कि वर्तमान से परे भी बहुत बड़ा संकट है और इस पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है? आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल आज बंगाल के स्वास्थ्य क्षेत्र में फैली गहरी सड़ांध का जीता जागता सबूत है। यह एक जघन्य आपराधिक कृत्य का गढ़ है और इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। जब नागरिक जागरूकता अभियान चल रहा था, तब भीड़ ने इसके परिसर पर हमला किया, जिससे परिसर के बड़े हिस्से में तोड़फोड़ की गई। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, आपातकालीन विंग में फर्नीचर को बहुत नुकसान पहुंचा है, साथ ही सीसीटीवी कैमरे और रेफ्रिजरेटर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिनमें लाखों रुपये की दवाएं रखी हुई हैं। बहाली को प्राथमिकता देना तार्किक पहला कदम होना चाहिए था।

फिर भी हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। उदाहरण के लिए, आरजी कार में दीदी की मौजूदगी, ऐसे प्रयासों की निगरानी करने से कम से कम विरोध करने वाले डॉक्टरों में आत्मविश्वास तो पैदा होता। हर दिन इलाज के लिए जिलों से कलकत्ता के सरकारी अस्पतालों में आने वाले अनगिनत मरीजों के लिए यह एक आश्वस्त करने वाला दृश्य होगा। यह एक छोटी सी शुरुआत होती, लेकिन फिर भी एक शुरुआत, शायद यह संकेत कि बंगाल में एक कार्यशील सरकार है जो जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटती। यह राज्य के लोगों के लिए भी एक शक्तिशाली संकेत होगा, जिसमें उनके आलोचक भी शामिल हैं, कि दीदी ने अपना रास्ता नहीं खोया है, कि उनके नेतृत्व में, बंगाल ने कुछ बहुत जरूरी, बड़े-टिकट सुधारों से अपनी नज़र नहीं हटाई है, जिन्हें किए जाने की आवश्यकता है, जैसे कि एक सिकुड़ती अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना, जिसके मूल में उद्योग की कमी है, सार्थक रोजगार पैदा करना, शासन से भ्रष्टाचार को खत्म करना और एक बड़े पैमाने पर लुम्पेनाइज्ड पार्टी कैडर बेस को ओवरहाल करना, जिसे नागरिक समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बताते हुए खैरात और जबरन वसूली के अधिकारों से सहारा दिया जा रहा है।

संस्कार बच्चें के अच्छें भविष्य का निर्माण...

हर माता-पिता सोचते हैं कि उनके बच्चे का भविष्य अच्छा हो, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं देते कि जब अच्छे चरित्र का निर्माण करेंगे, तो ही अच्छे भविष्य का निर्माण हो पाएगा। स्वाभाविक है कि अच्छे चरित्र के निर्माण की शुरुआत माता-पिता से होती है। माता-पिता बचपन से ही कोशिश कर रहे होते हैं कि बच्चों को अच्छा सिखाएं। लेकिन इस बात पर ध्यान नही देते हैं कि बच्चे वह नहीं सीखते जो आप कहते हैं वे वही सीखते हैं जो आप करते हैं। अधिकांश माता-पिता के लिए पालन-पोषण का अर्थ केवल बच्चों के भोजन, कपड़े और दैनिक जरूरतों की पूर्ति करना है। और इस तरह से माता-पिता अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन क्या माता-पिता अपने बच्चों को अच्छी आदतें या संस्कार दे पाते हैं जिससे कि उनके अच्छे चरित्र का निर्माण हो सके, ताकि वे भविष्य में एक बेहतर जीवन जी सकें। जिससे कि उन्हें जीवन जीने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

(स्वतंत्र छत्तीसगढ़)

हर पीढ़ी के बच्चों में बदलाव आता है और ऐसे में यदि आप अपने बच्चे के प्रति सचेत नहीं हैं तो आप नई पीढ़ी के भविष्य निर्माण से चूक जाएंगे जो कि भविष्य में एक माता-पिता होने के नाते आपके लिए पीड़ा दायक हो सकता है। इसलिए आपको आज से ही सोचना होगा कि ऐसा क्या करना चाहिए. जिससे कि भविष्य में आपको खुशी मिले। जब तक आप माता-पिता नहीं थे तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन माता-पिता बनने के बाद आप पर रचनात्मक जिम्मेदारी आ गई है। एक पूरा जीवन बनेगा या बिगड़ेगा यह आप पर निर्भर करता है। माता-पिता बनने के बाद आप जो कुछ भी करते हैं उसका प्रभाव बच्चे के भविष्य पर अवश्य पड़ता है।

मानव जीवन में चरित्र का विशेष महत्व है और चरित्र ज्ञानवान होने से बनता है, यदि मनुष्य में ज्ञान नहीं है तो चरित्र का कोई अर्थ नहीं है। हम अपने घर, परिवार, समाज, देश और विदेश में व्यापार और नौकरी करते हैं, इन सब में ज्ञान और अच्छे चरित्र का होना एक श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति की पहचान है। जैसा कि हम जानते हैं कि चरित्र कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम कहीं से खरीद कर प्राप्त कर सकें। लेकिन सकारात्मक सोच ही हमें ऊंचाई के शिखर पर ले जाती है साथ ही अच्छे चरित्र का निर्माण भी करती है।

हमारे मन में दो प्रकार के विचार होते हैं, एक अच्छे विचार और दूसरे बुरे विचार लेकिन अगर हम अपने आप में यह निश्चय कर लें कि हम कभी भी नकारात्मक विचारों को अपने मन पर हावी नहीं होने देंगे और हर काम अच्छा ही करेंगे तो यही एक अच्छा चरित्र है। किसी व्यक्ति के अच्छे चरित्र के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका उसके घर के वातावरण की होती है। क्योंकि बच्चों को स्कूल में किताबी ज्ञान मिलता है, बच्चों में अच्छे संस्कार रखने का श्रेय उनके माता-पिता को जाता है कि उन्होंने अपने बच्चों को कैसी तालीम दी है। बच्चे बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था को प्राप्त करते हैं, फिर विवाह होता है और घर की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। परिवार चलाना और जीवन की सारी गतिविधियां पैसे पर आधारित होती हैं, इसलिए पैसा कमाना भी बहुत जरूरी है। लेकिन एक सफल जीवन जीने के लिए पैसा कमाना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए, जीवन को सफल और आदर्श परिवार बनाने के लिए और अधिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। अक्सर देखा गया है कि अन्य बातों को छोड़कर लोगों का एक ही सपना होता है कि बहुत सारा पैसा कैसे कमाया जाए।

यदि हम इस प्रकार की सोच रखते हैं तो परिवार और बच्चे ठीक से जीवन जीने की कलाओं से वंचित रह जाते हैं। जिसका परिणाम बच्चों के साथ-साथ माता-पिता के लिए भी बहुत बुरा होता है। पैसा कमाने के साथ-साथ यदि हम सोचते हैं कि हमारा परिवार और बच्चे आदर्श हों तो हमें इन सब बातों पर ध्यान देना होगा। उन्हें आचरण में लाना होगा। तभी हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे बच्चे आदर्श और संस्कारी होंगे। हम जैसा बीज बोयेंगे, जैसा व्यवहार करेंगे, जैसा वातावरण देंगे, हमें वैसा ही फल भी मिलेगा।

वर्तमान में बदलती जरूरतों के साथ साथ युवाओं को भी प्रशिक्षित होना चाहिए ...

(स्वतंत्र छत्तीसगढ़)

दुनिया तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। कामकाज के तरीके तेजी से डिजिटल और स्वचालित हो रहे हैं। रोबोटिक शक्ति इसका आधार बन रही है। कृत्रिम मेधा भी मुख्य सहयोगी के रूप में उभर रही है। यानी भारत में उत्पादन, निवेश और खेती-किसानी के तरीके भी बदलेंगे।

विशेषज्ञों के अनुसार अगले दस सालों में कामकाज के घंटों और नौकरी करने के तौर-तरीकों में परिवर्तन आएगा। एआई और रोबोटिक्स के चलते स्थायी व्यवस्था की जगह गिग अर्थव्यवस्था सामने आएगी। इसमें जरूरत के अनुसार अस्थायी कर्मचारियों को काम पर रखने का चलन बढ़ेगा। इसके साथ ही, काम के घंटे बदलने के कारण पारंपरिक नौकरियों की व्यवस्था के अतिरिक्त कर्मचारी संविदा के आधार पर विभिन्न सेक्टरों-कंपनियों में एक साथ कई जिम्मेदारियां संभाल सकेंगे। इसका असर डिजिटल और इंटरनेट की दुनिया में अभी से दिखने लगा है। आईटी एक्सपर्ट वर्क फॉम होम करते हुए एक साथ कई कंपनियों का काम संभाल रहे हैं। पिछले दिनों एक प्रस्ताव सामने आया था कि काम के घंटे 10 से 14 कर दिए जाएं, क्योंकि आईटी क्रांति का सामना इसी तरह से किया जा सकेगा। बहरहाल, कामकाजी दुनिया की हकीकत बदल रही है।

हाल के बजट में वित्तमंत्री ने भी जिन पांच क्षेत्रों में नौकरी की व्यवस्था पर ध्यान केन्द्रित किया है, उसमें कृत्रिम मेधा और रोबोट्स की दुनिया के प्रयोग को नकारा नहीं है। भारत, जिसकी आबादी इस समय दुनिया में सबसे अधिक है, क्या वह कृत्रिम मेधा या रोबोट का उपयोग उसी तरह कर सकता है जैसे शक्ति-संपन्न पश्चिमी देश करते हैं, जहां आबादी की कमी है। बजट सत्र में वित्तमंत्री ने नई नौकरियों के लिए दो लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके द्वारा अगले पांच साल में 4.1 करोड़ नौजवानों को विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे रोजगार की दुनिया में खुद को अनुकूलित कर सकें।

देश में आज भी आधी आबादी से कम खेतीबाड़ी में लगी हुई है। प्रश्न है कि वहां से सकल घरेलू आय में केवल 15 प्रतिशत का योगदान ही क्यों मिल रहा है? आंकड़े बता रहे हैं कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर बढ़ी है। इसके अतिरिक्त , ऐसे बेरोजगार भी हैं जो पारंपरिक तरीके से अपनी पैतृक खेतीबाड़ी के धंधे में लगे रहते हैं, लेकिन देश की निवल आय में उनका कोई योगदान नहीं है। इस अनुपयोगी युवा शक्ति का इस्तेमाल किसी ऐसे वैकल्पिक धंधे में होना चाहिए जो उन्हें ग्रामीण स्तर पर ही वहीं काम उपलब्ध करवा दे।

लघु और कुटीर उद्योगों का विकास और फसलों को पूर्ण रूप से तैयार करके सीधे मंडी में बेचना भी एक समाधान हो सकता है। बजटीय घोषणाओं में अगले वर्ष अखिल भारतीय सहकारी अभियान चलाने का वादा है। इसके अंतर्गत इन सभी लोगों को काम मिलेगा। लघु-कुटीर उद्योगों की बातें तो होती हैं लेकिन लाल डोरा क्षेत्र में भी ग्रामीण युवा शक्ति के स्थान पर शहरी निवेशक ही प्रवेश करता नजर आता है।

निस्संदेह, जब निजी क्षेत्र का विकास होगा और नये कारखाने खुलेंगे या फसलों पर आधारित छोटे उद्योग बढ़ेंगे, तो लोगों को स्वाभाविक रूप से रोजगार मिल जाएगा। सरकार द्वारा नौकरियां देने की क्षमता बहुत कम है। बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का प्रतिशत 30 से अधिक नहीं रहा। आर्थिक प्रोत्साहन और नए निवेश के बावजूद देश अधिक से अधिक हर साल 70 लाख नौकरियां ही प्रदान कर पाएगा, जबकि देश के युवाओं को हर वर्ष कम से कम एक करोड़ नौकरियों की आवश्यकता पड़ेगी। क्या निजी क्षेत्र, सरकार के सभी प्रोत्साहनों, सब्सिडियों, मुद्रा योजनाओं और लोन क्षमता बढ़ाने के बावजूद इस कसौटी पर पूरा उतर सकेगा? बेशक, इस बार के बजट में मुद्रा योजना के तहत कर्ज की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख प्रति इकाई कर दी गई है। नया प्रशिक्षण प्राप्त करने की इंटर्नशिप पर सबसिडी भी दी जा रही है। लेकिन क्या इतना काफी है?

देश में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों को अभी भी उचित महत्व नहीं दिया जा रहा। शिक्षा बजट में केवल सवा लाख करोड़ रुपये और सेहत पर केवल 89 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। यह युवा शक्ति को स्वस्थ-शिक्षित नागरिक बनाने हेतु काफी नहीं है।

शिक्षाविदों के अनुसार, पुरानी शिक्षा पद्धति से निकले हुए 75 प्रतिशत ग्रेजुएट्स नई डिजिटल व्यवस्था में नौकरी के योग्य नहीं हैं। इसलिए, युवा शक्ति को अपनी डिग्री से कहीं नीचे के काम करने के लिए समझौता करना पड़ता है। देश में काम देने में असंगठित क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन डिजिटलीकरण के साथ असंगठित क्षेत्र भी बिखरता नजर आ रहा है। जरूरी है कि बेरोजगारों के संघर्ष को बेहतर ढंग से समझा जाए और बदलते समय की मांगों के अनुसार युवा शक्ति को प्रशिक्षित करके उसे सही दिशा में कार्यशील बनाया जाए।

हमेशा की तरह पीएम मोदी ने अपने भाषण में नेशन फर्स्ट की बात कही ...

मजबूत सरकार का पता तो उसके तेवर से ही चलता है। पीएम मोदी ने स्वतन्त्रता दिवस पर लाल किले से दिए भाषण में वही तेवर दिखाए जो पिछले 15 अगस्त थे। उनकी कही गई बातों से कतई नहीं लगा कि वे साझा कमजोर सरकार के पीएम हैं। हमेशा की तरह उन्होंने अपने भाषण मे संकेत दिया कि इस साल वह क्या करने वाले हैं तथा आने वाले समय में वह क्या करना चाहते है। यह पी.एम. मोदी की खासियत है कि वह कोई भी बड़ा काम करते हैं तो उसके संकेत पहले दे देते हैं। जो समझदार लोग है,वह समझ जाते हैं कि आने वाले दिन में पीएम मोदी क्या बड़ा करने वाले हैं। इस पांच साल में सरकार क्या क्या बड़ा काम कर सकती है।

कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब तो साझा सरकार है, वह भ्रष्टाचार के मामले में पहले जैसे मजबूती से काम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने संसद में भी कहा था कि भ्रष्टाचार के मामले में पहले की तरह कार्रवाई की जाएगी। अब स्वतंत्रता दिवस के भाषण में भी उन्होने दोहराया कि भ्रष्टाचार करने वाले के खिलाफ तेजी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए नया ई.डी. का डायरेक्टर भी चुन लिया गया है. माना जाता है कि राहुल नवीन भी ईमानदार व भ्रष्टाचार करनेवालों को बक्शने वाले अधिकारी नहीं है। वह वैसे ही अधिकारी है जैसे पिछले सरकार में थे। मानने वाले तो इसे भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ाई करने का संकेत मान रहे है। बीच में राहुल गांधी ने जो रात को कहा था कि मुझे भी गिरफ्तार किया जा सकता है, हो सकता हो उनको कहीं से भनक लग गई हो। राहुल नवीन को ईडी का नया डायरेक्टर बनाया जा रहा है।

हमेशा की तरह पीएम मोदी ने अपने भाषण में नेशन फर्स्ट की बात कही है। पीएम मोदी शुरू से ही सर्वप्रथम देश की बात करते रहे हैं। देखा जाए जो उनको अपने काम का राजनीतिक लाभ जरूर मिला है लेकिन उन्होंने कई काम राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किए हैं। वह देश हित में देश के लिए काम करने वाले नेता हैं, चाहे धारा-370 हटाना हो, नोटबंदी लागू करना हो,जीएसटी लागू करना हो, अग्निवीर योजना हो, वक्फ संशोधन बिल हो, पुराने कानून समाप्त करना हो, उनकी जगह नए कानून बनाना हो, सब सुधार के काम है। देश के हर क्षेत्र में सुधार की जरूरत है और पिछली जितनी सरकारे रहीं है चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो या गैर कांग्रेस सरकार, वह सुधार करना नहीं चाहते थे या सुधार करने लायक नही थे। बहुमत की सरकार है इसलिए पीएम मोदी यह सुधार का काम कर पा रहे हैं, जनता उन्हें चुनती ही इसलिए है कि वह जानती है कि यही एक ऐसा नेता है जो चाहता है कि भारत के जिस क्षेत्र में भी सुधार की जरूरत है, वह कैसे किया जा सकता है।

अपने भाषण में उन्होने एक नेशन-एक चुनाव की बात कही है तो यह भी देशहित में किया जाने वाला काम है। उन्होंने इस बार एक नए शब्द की प्रयोग किया है, वह है सेकुलर यूसीसी। उनका कहना है कि देश में जो समान नागरिक संहिता लागू है, वह सांप्रदायिक है, वे उसकी जगह सेकुलर यूसीसी लाना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए देश में चर्चा की जरूरत बताई है तथा कहा है कि वह चाहते हैं कि हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोग इस पर अपना सुझाव दे, उसके सभी के सुझाव के आधार पर देश में एक सेकुलर यूसीसी लागू किया जाएगा। यह एक तरह से कांग्रेस पर उसी के हथियार से किया गया हमला है।

कांग्रेस घर्मनिरपेक्षता के हथियार से भाजपा पर हमला करती रही है और उसे सांप्रदायिक बता कर राजनीति में अछूत बनाए रखा था। अब मोदी उसी घर्मनिरपेक्षता के हथियार से कांग्रेस पर हमलावर है और उसे सांप्रदायिक राजनीति करने वाली पार्टी बता रहे हैं। यह सच भी है कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता की आड़ में मुस्लिम तुष्टिकरण किया है तो यह सांप्रदायिक राजनीति तो है। देश मे हिंदू कोड बिल लाया गया और मुसलमान को छोड़ दिया गया। समान नागरिक संहिता तो तब होती जब दोनों के लिए समान कानून लाया जाता। इसी को तो पीएम मोदी सांप्रदायिक यूसीसी कह रहे है। वह सेकुलर यूसीसी लाने की बात कर रहे है तो उसमें सभी के लिए समान कानून होगा।

अब कांग्रेस सेकूलर यूसीसी का विरोध कर नहीं सकती। क्योंकि माना जाएगा कि वह सेकुलर नहीं है, इसलिए सेकुलर यूसीसी का विरोध कर रही है। अपने 15 अगस्त के भाषण में मोदी ने वह सब बताया है जो वह भारत के लिए करना चाहते थे और किया है, और वह सब भी बताया है जो विकसित भारत के लिए करना चाहते है। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य विकसित भारत है। इसी की बात कर मोदी देश के सबसे बड़े नेता बन जाते हैं क्योंकि और कोई नेता विकसित भारत की बात नहीं करता है। वह जाति की बात करते है, आरक्षण की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते है, संविधान की बात करते हैं तो वह यह नहीं बता पाते हैं कि इससे देश का कैसे विकास होगा, देश कैसे बड़ा बनेगा। यही बड़ा फर्क है पीएम मोदी व देश के बाकी नेताओं में, मोदी देश को बड़ा बनाना चाहते हैं और बाकी नेता खुद को बड़ा बनाना चाहते हैं।

हेल्थ-टिप्स- हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है कद्दू...

कद्दू में पोटैशियम, विटामिन, फाइबर, फोलेट और मैग्निशियम जैसे पोषक तत्वों की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। अगर आप रेगुलरली कद्दू की सब्जी का सेवन करते हैं, तो आप कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का शिकार बनने से बच सकते हैं। इतना ही नहीं कद्दू की सब्जी आपकी हेल्थ के साथ-साथ आपकी स्किन के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकती है।

कद्दू आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है यानी आप दिल से जुड़ी जानलेवा बीमारियों के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा कद्दू की सब्जी आपके लिवर को भी हेल्दी बनाए रखने में मददगार साबित हो सकती है। आयुर्वेद के मुताबिक कद्दू की सब्जी पीलिया को ट्रीट करने में भी कारगर साबित हो सकती है। अगर आपको बुखार है तो भी आप कद्दू को अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं।

मिलेंगे फायदे ही फायदे

कद्दू की सब्जी तनाव से होने वाले सिर दर्द को कम करने में कारगर साबित हो सकती है। कद्दू की सब्जी का सेवन कर आप कब्ज और बवासीर जैसी पेट से जुड़ी समस्याओं को भी अलविदा कह सकते हैं। अगर आप अनिद्रा की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो कद्दू का सेवन करना शुरू कर दीजिए।

पपीता खाने के बाद भूलकर भी न करें डेरी प्रोडक्ट का सेवन...

पपीता में कई पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन क्या आपको पता है सेहत के लिए बेहतरीन होने के बावजूद भी पपीते का सेवन कई चीजों के साथ नहीं करना चाहिए। ऐसा करना आपकी सेहत के लिए घातक हो सकता है। जानिए ये चीजें क्या हैं और इनका पपीते के साथ सेवन करना क्यों हानिकारक है।

पपीता खाने के बाद आपको डेरी प्रोडक्ट्स जैसे- दूध और दही, पनीर का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दरअसल, पपेन दूध में कैसिइन (कैसिइन प्रोटीन दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है जो दूध को सफ़ेद रंग देता है) को तोड़ सकता है। इस वजह से आपका पेट खराब हो सकता है और आप कब्ज, बदहजमी, ब्लोटिंग और दस्त के शिकार हो सकते हैं। इसलिए, पपीता खाने के बाद दूध पीने से बचना चाहिए।

पपीता खाने के बाद चाय न पिएं- पपीता खाने के बाद चाय भूलकर भी नहीं पीनी चाहिए। दरअसल, पपीता का पपेन कम्पाउंड और चाय की पत्तियों में मौजूद कैटेचिन रिएक्ट कर सकता है।इस वजह से सीने में जलन, अपच और गैस्ट्रिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

अंडा न खाएं- पपीता खाने के बाद अंडा नहीं खाना चाहिए। जहां अंडा प्रोटीन और ओमेगा-3 से भरपूर है वहीं पपीता पपेन एंजाइम से भरपूर होता है।ऐसे में दोनों को एक समय पर खाने से बदहजमी, मतली, कब्ज और उल्टी की समस्या हो सकती है.

न करें नींबू का सेवन- पपीता खाने के बाद नींबू का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए।पपीते कहने के तुरंत बाद आप इसका सेवन करते हैं यो शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल बिगड़ सकता है। इस वजह से एनीमिया का खतरा भी बढ़ सकता है।

उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थ- पपीते के बाद बीन्स, गोभी या ब्रोकली जैसे उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थों का सेवन पाचन संबंधी समस्याओं को और भी बदतर बना सकता है।

करोड़ों के मालिक आखिर क्यों कर रहे हैं 81 की उम्र में भी काम? अब पता चली असली वजह

सुपरस्टार अमिताभ बच्चन लगातार फिल्मों में काम किए जा रहे हैं. 81 साल की उम्र में भी दिग्गज एक्टर इंडस्ट्री के सबसे बिजी स्टार्स में से एक हैं.अक्सर लोग उनसे सवाल करते हैं कि उम्र के इस पड़ाव में भी वो काम क्यों कर रहे हैं, जिसका जवाब एक्टर ने अपने ब्लॉग में दिया है.

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन 81 साल के हैं. उम्र के इस पड़ाव में भी वो इंडस्ट्री में पूरी तरह से एक्टिव हैं और ऑडियंस का मनोरंजन कर रहे हैं. फिल्मों के साथ ही वो टीवी के हिट शो 'कौन बनेगा करोड़पति' को होस्ट कर रहे हैं. किसी यंग एक्टर की तरह बिग बी में भी एक्टिंग को लेकर वही जोश और जज्बा है. हाल ही में बिग बी ने बताया कि उनसे अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि वो 81 साल की उम्र में भी क्यों काम कर रहे हैं.

हाल ही में चक्क्ष्ट के दौरान भी अमिताभ से यही सवाल एक बार फिर से पूछा गया. जिसका जवाब उन्होंने बेहद खूबसूरती के साथ दिया. उन्होंने कहा कि वो इसलिए काम कर रहे हैं क्यों कि उन्हें अभी भी काम मिल रहा है. उन्होंने अपने नए ब्लॉग में कहा है कि लोग अक्सर उनसे पूछते हैं कि इतना काम करने की वजह आखिर क्या है. बिग ने जवाब देते हुए कहा कि उनके पास इस सवाल का कोई खास जवाब नहीं है, सिवाय इसके कि उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है. इसका और क्या कारण हो सकता है.

'लोगों के पास उनकी कंडीशंस होती हैं'

सदी के महानायक ने कहा कि लोगों के पास उनकी कंडीशंस होती हैं. कुछ लोग अक्सर अपने रोल मॉडल को फॉलो करते हैं. आगे उन्होंने कहा कि मेरी जगह आकर देखिए और पता लगाइये, शायद आप सही हों या नहीं, आपको अपना जवाब ढूंढने की आजादी और मुझे मेरा काम करने की. बिग बी ने कहा कि मुझे काम मिल रहा है इसलिए मैं काम कर रहा हूं. हो सकता है मैरी इस बात से कुछ लोग सहमत न हों. लेकिन हर किसी को बोलने की आजादी है तो हर किसी की बात सुनी जाएगी. सीनियर बच्चन यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा कि पर्मानेंसी का उपाय ढूंढिए. अगर ये आपके या आपके बिजनेस के लिए है. मेरा हो गया मैं अभी भी डटा हुआ हूं, अपना काम करता हूं, आपको इससे कोई परेशानी?.

फिल्म 'सात हिंदुस्तानी' से करियर की शुरुआत

मिलेनियर स्टार अमिताभ बच्चन ने फिल्म 'सात हिंदुस्तानी' से अपने करियर की शुरुआत की थी. ये फिल्म 1969 में रिलीज हुई थी.अपने 55 सालों के करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी. अपनी दमदार एक्टिंग के जरिए उन्होंने ऑडियंस के दिलों में वो मकाम बनाया जहां इंडस्ट्री का हर एक्टर पहुंचना चाहता है. आज भी वो उसी जोश और जुनून के साथ काम कर रहे हैं.

हाल ही में उनकी 'कल्कि 2898 एडी' रिलीज हुई थी. जिसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की. इस फिल्म में बिग बी के साथ साउथ के सुपरस्टार प्रभास और दीपिका पादुकोण ने अहम भूमिका निभाई थी. फैंस ने इस फिल्म को काफी पसंद किया. इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन के काम की भी काफी तारीफ हुई थी.